

न्यू इंडिया

समाचार



वर्ष

@NISPIIndia

हमें फॉलो करें

विकास का विजन देश का मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित करने वाला रहा है। इस दौरान देश ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान का किया है अनुभव...



ई-कॉपी
के लिए QR
स्कैन करें

विश्व पर्यावरण दिवस : 5 जून

भारत की संस्कृति में प्रकृति भी और प्रगति भी

भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में, प्रकृति के साथ-साथ प्रगति भी मौजूद है। हमारे पूर्वजों की कामना थी - पृथ्वी: पूः च उर्वी भव। अर्थात् संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण परिवेश हम सभी के लिए उत्तम हो। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए आज जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर उभरा है। जलवायु और पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्र और नागरिक संगठित प्रयास से ही हम आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे सुरक्षित पर्यावरण...

“

विकास और पर्यावरण में संतुलन हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन, वयष्टि और समष्टि का संतुलन, जीव और शिव का संतुलन हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। हम जो भी अपने लिए करते हैं, उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने संसाधनों की दक्षता को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



अंदर के पन्नों पर...

न्यू इंडिया समाचार

वर्ष: 6, अंक: 23 | 1-15 जून, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह



13 भाषाओं में उपलब्ध
न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने
के लिए क्लिक करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

न्यू इंडिया समाचार के पुराने
अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx>

X न्यू इंडिया समाचार के बारे में
लगातार अपडेट के लिए फॉलो
करें: @NISPIBIndia



12 वर्षीय संकल्प यात्रा

विकसित भारत की यात्रा का एक नवयुग

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 2014 से 2026 एक ऐसे युग का पर्याय बन गया है जिसने संकल्पों की सिद्धि का नया अध्याय लिखा है। यह साक्षी बन गया है क्रांतिकारी परिवर्तनों का और आज देश का जन-जन इन परिवर्तनों में खुद को कर पा रहा है सहभागी महसूस... | 8-68

सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष

सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत की अडिग भावना का उत्सव



गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का किया उद्घाटन... | 72-74

व्यक्तित्व : दामोदर मेनन

जिन्होंने पत्रकारिता को हथियार बना लड़ी आजादी की लड़ाई | 4

खरीफ फसलों की एमएसपी व दो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय | 5-7

बेंगलुरु ने अध्यात्म और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊंचाई तक पहुंचाया
द आर्ट ऑफ लिविंग के स्थापना समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी | 69

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा भारत



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन | 70-71

संपादक की कलम से...

सर्वांगीण-सर्वसमावेशी-सर्वस्पर्शी

जनसेवा, जनविश्वास, जन कल्याण के 12 वर्ष

सादर नमस्कार।

26 मई 2014 की वह संध्या भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई, जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को शपथ लिया था। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का एक व्यापक अभियान रहा है। इन वर्षों में शासन का केंद्र हमेशा देश का नागरिक रहा और गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति को विकास की सबसे बड़ी शक्ति माना गया।

सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसका एक बड़ा उदाहरण रही।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कालखंड ऐतिहासिक रहा है। भारत की प्राचीन योग परंपरा को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में वैश्विक पहचान मिली, जिसे आज पूरी दुनिया अपना चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कई साहसिक निर्णय लिए।

रोजगार और उद्यमिता में भी भारत ने नई पहचान बनाई है। देश के युवा अब केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और मोबाइल निर्माण में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। डिजिटल इंडिया ने शासन को पारदर्शी

और सुलभ बनाया है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज रियल-टाइम डिजिटल भुगतान करने वाला देश बन चुका है। साथ ही, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनेक देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं।

इन 12 वर्षों में सरकार ने केवल पहले की कमियों को दूर नहीं किया, बल्कि वर्तमान को भी मजबूत करते हुए विकसित भारत@2047 का स्पष्ट लक्ष्य भी देश के सामने रखा है। इस प्रकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ केंद्र सरकार निरंतर जनसेवा, जनविश्वास और जनकल्याण के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष की यात्रा ही इस बार की हमारी आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पत्रकारिता को हथियार बना कर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दामोदर मेनन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर 5 जून को होने वाले पर्यावरण दिवस और बैंक कवर पर राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपील पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)



हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

आपकी बात...



लोगों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन

मैं न्यू इंडिया समाचार के जरिए किए जा रहे बेहतरीन काम के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सच में एक शानदार न्यूजलेटर है, जो सभी भारतीय भाषाओं, खासकर तमिल में उपलब्ध होने से और भी खास हो गया है। इससे देश भर के लोग हमारी सरकार की जरूरी पहलों, उपलब्धियों और विजन को आसानी से समझ और उनसे जुड़ पाए हैं। मैं खासतौर पर इस बात की तारीफ करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और सरकार के अलग-अलग प्रोग्राम से जुड़ी सभी जरूरी खबरें न्यू इंडिया समाचार के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर लाई जाती हैं। यह लोगों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। देश को असली और प्रेरणा देने वाली खबरें देने में आपका समर्पण और कमिटमेंट बहुत तारीफ के काबिल है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को आने वाले सालों में लगातार सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ।

एस. राजेशकन्ना

kisanmorcha.gs@gmail.com

सरकारी नीतियों और पहलों के बारे में मिलती है जानकारी

मैं 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका नियमित रूप से पढ़ती हूँ। सरकारी नीतियों और पहलों के बारे में जानकारी रखने के लिए मुझे इस पत्रिका को पढ़ने में बहुत रुचि है। मैं पढ़ी गई जानकारी को अपने आसपास के सभी लोगों के साथ साझा करती रहती हूँ।

पारुल शर्मा

ps308616@gmail.com

अच्छी पत्रिका है न्यू इंडिया समाचार

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका अच्छी है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है।

ओम लता अखौरी

omlata.akhouri@gmail.com

पत्रिका से मिलती है विस्तृत जानकारी

'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका के 16-30 अप्रैल 2026 अंक में 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आग्रह' पढ़ा तो प्रेरित हुआ। क्योंकि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के स्वास्थ्य, समृद्ध तथा विकास के लिए हरेक क्षेत्र पर अपनी नजर रखी है और यथोचित सलाह से हमारा मार्गदर्शन भी किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संपादक की कलम से... अंतर्गत 'भारत से लाल आतंक का खात्मा' की विस्तृत जानकारी मिली जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजादी के बाद निरंतर नक्सली हमलों के कारण आदिवासी इलाके का विकास रूक गया था और जनधन के नुकसान के साथ भारी संख्या में हमारे जवानों की जानें गईं। मोदी सरकार ने सही फैसला लेकर मुहिम चलाई और भारत को नक्सल मुक्त बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए देशवासियों में मोदी सरकार की नीति और निर्णय पर विश्वास बढ़ा है।

बिर्ख खडका डुवसेली

birkhakd@gmail.com

आर्थिक नीतियों की विस्तृत कवरेज अत्यंत जानकारीपूर्ण

मैं 'न्यू इंडिया समाचार' के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। एक कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर, मुझे इस पत्रिका में राष्ट्रीय विकास, सरकारी योजनाओं और आर्थिक नीतियों की विस्तृत कवरेज अत्यंत जानकारीपूर्ण और मेरे पेशेवर क्षेत्र के लिए बेहद प्रासंगिक लगती है। पेशेवर समुदाय को सूचित रखने के आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद।

धर्मेश बेलडिया

dbeladiya32@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in



जिन्होंने पत्रकारिता को हथियार बना लड़ी आजादी की लड़ाई

जन्म : 10 जून 1906, मृत्यु : 1 नवंबर 1980

भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी के. ए. दामोदर मेनन ने देश की आजादी के दौरान न केवल सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जमकर आवाज भी उठाई। लंबे समय तक मातृभूमि अखबार से जुड़ कर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रभावशाली लेखन किया। पत्रकारिता में निर्भीकता, ईमानदारी, निष्पक्षता और लोक हित के प्रति समर्पण उनकी पहचान थी जिसे आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना मजबूत हथियार बनाया। स्वतंत्रता के बाद राजनीति से जुड़ने एवं जनसेवा का ध्येय लेकर चलने वाले दामोदर मेनन ने जनजागरण, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में दिया महत्वपूर्ण योगदान...

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता करने वाले के. ए. दामोदर मेनन भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 10 जून 1906 को केरल (अब केरलम) के करमलूर में जन्मे मेनन का जीवन सत्य, निष्ठा और सेवा के मूल्यों का प्रतीक रहा। उन्होंने महाराजा कॉलेज, त्रिवेंद्रम और रंगून यूनिवर्सिटी, बर्मा (वर्तमान म्यांमार) से शिक्षा पाई थी। इसके बाद उन्होंने त्रिवेंद्रम से कानून की डिग्री ली। शिक्षा के बाद उनकी रुचि सार्वजनिक कार्यों के साथ-साथ पत्रकारिता में अधिक होने लगी थी। ऐसे में वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता-संग्राम में सम्मिलित हो गए।

दामोदर मेनन के जीवन पर महात्मा गांधी और उनके विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 'नमक सत्याग्रह' और 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। जेल में भी रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में न सिर्फ भाग लिया बल्कि इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। यही कारण है कि अंग्रेजों ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और वे 1942

से 1945 तक जेल में बंद रहे।

दामोदर मेनन ने 1948 तक प्रसिद्ध मलयालम दैनिक 'मातृभूमि' के संपादक के रूप में जन-जागरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के दमन की आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने अलग-अलग समय में 'समदर्शी', 'स्वतंत्र', 'कहालम' और 'पावर शक्ति' पत्रों का भी संपादन किया। भारत की आजादी के बाद भी वह राष्ट्र हित के लिए काम करते रहे। लोकसभा एवं विधानसभा के लिए भी चुने गए।

केरल विधानसभा के सदस्य चुने जाने के बाद वह राज्य सरकार में मंत्री भी बने। माना जाता है कि उनके आर्थिक विचार बड़े उदार थे। वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। इसीलिए वे अंतरजातीय ही नहीं, भिन्न धर्मावलंबियों के बीच विवाह-संबंधों के भी समर्थक थे। 1 नवंबर 1980 को उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2022 को मातृभूमि अखबार के शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन समारोह में दामोदर मेनन को याद किया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। ■

खरीफ फसलों की एमएसपी और दो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी



देशभर के किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत दो और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी दी मंजूरी...

निर्णय : विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी।

प्रभाव : सरकार ने वर्ष 2026-27 के विपणन सीजन के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी के बीज (622 रुपये प्रति क्विंटल), उसके बाद कपास (557 रुपये प्रति क्विंटल), नाइजरसीड (515 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल के लिए (500 रुपये प्रति क्विंटल) संस्तुति की गई है।

निर्णय : भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत दो और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : मंजूर किए गए दो प्रस्तावों से गुजरात में लगभग 3,936 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएंगी। इनसे कुशल पेशेवरों के लिए कुल 2,230 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

- इन दोनों अनुमोदनों के साथ, देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आईएसएम के तहत कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या 12 तक पहुंच जाएगी, जिनका कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

- ये देश में उभरती विश्व स्तरीय चिप डिजाइन क्षमताओं में पूरक भूमिका निभाएंगी, जिन्हें सरकार द्वारा 315 शैक्षणिक संस्थानों और 104 स्टार्टअप को प्रदान किए गए डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन से गति मिली है।
- भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की गति और बढ़ रही है, क्योंकि दस अनुमोदित परियोजनाएं पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

निर्णय : आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को मंजूरी।

प्रभाव : इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों से व्यवसायों को उबरने में सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त, इससे व्यवसायों को अपना परिचालन बनाए रखने, नौकरियों की रक्षा करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

- प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- समय पर पैसे उपलब्ध कराकर यह योजना व्यवसायों को बनाए रखेगी और नौकरियों के नुकसान को रोकेगी।
- यह निर्बाध घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगी और इकोसिस्टम की सुदृढ़ता को भी बनाए रखेगी।

निर्णय : आर्थिक कार्य समिति ने गुजरात के वडीनार में जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी।

प्रभाव : वडीनार जहाज मरम्मत केंद्र भारत के जहाज मरम्मत इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद एक महत्वपूर्ण कमी को सीधे तौर पर दूर करेगी। दरअसल, देश में वर्तमान में 230 मीटर से अधिक लंबाई वाले बड़े जहाजों की मरम्मत के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता का अभाव है। 300 मीटर तक के जहाजों की मरम्मत को सक्षम बनाकर, यह केंद्र भारत के भीतर ही बड़े जहाजों की उच्च-मूल्य वाली मरम्मत को संभव बनाएगी। इससे विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता काफी कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।

- इस परियोजना से जहाज मरम्मत, रसद और सहायक उद्योगों में लगभग 290 प्रत्यक्ष और लगभग 1,100 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना। साथ ही, यह व्यापक समुद्री औद्योगिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगी।

निर्णय : मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 19 जिलों को शामिल करने वाली 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

प्रभाव : इससे भारतीय रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 23,437 करोड़ रुपये है। यह वर्ष 2030-31 तक पूरी हो जाएगी।

- प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 4,161 गांवों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, जिनकी आबादी लगभग 83 लाख है।

इन परियोजनाओं में शामिल

नागदा-मथुरा तीसरी और चौथी लाइन।

गुंतकल-वाडी तीसरी और चौथी लाइन।

बुरहवाल-सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन।



निर्णय : संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

प्रभाव : इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है।

- न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा। इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।
- न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत की संवित निधि से पूरा किया जाएगा।

निर्णय : गन्ना किसानों के लिए वर्ष 2026-27 चीनी उत्पादन सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल स्वीकृत।

प्रभाव : गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ ही चीनी मिलों और संबंधित सहायक कार्यों में लगे 5 लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे।

निर्णय : नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी।

प्रभाव : नागपुर हवाई अड्डे के लिए नागपुर में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट (मिहान) परियोजना के तहत क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निजी क्षेत्र की दक्षता और सरकारी निगरानी के साथ, हवाई अड्डे में महत्वपूर्ण निवेश, आधुनिकीकरण और बेहतर यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं की संभावना है।

- चरणबद्ध विकास के तहत इसकी अंतिम क्षमता 30 मिलियन यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने की होगी, जिससे यह मध्य भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा।
- यह परिवर्तन न केवल विदर्भ क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि इसके आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। इससे माल ढुलाई क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।



कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

निर्णय : 37,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से सतह के निकट स्थित कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति।

प्रभाव : यह योजना भारत के कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने, वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।

- साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और तरलीकृत प्राकृतिक गैस - एलएनजी (50 प्रतिशत से अधिक आयात), यूरिया (20 प्रतिशत आयात), अमोनिया (100 प्रतिशत आयात) और मेथनॉल (80-90 प्रतिशत आयात) जैसे प्रमुख उत्पादों की आयात निर्भरता कम करने में मदद करेगा।

निर्णय : गुजरात के अहमदाबाद जिले को शामिल करने वाली एक नई परियोजना को मंजूरी दी।

प्रभाव : इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 134 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 20,667 करोड़ रुपये है। यह 2030-31 तक पूरी हो जाएगी

- इस परियोजना खंड से अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, धोलेरा का आगामी हवाई अड्डा और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा।
- अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम

होगा, जिससे दैनिक आवागमन आरामदायक होगा और एक ही दिन में वापसी यात्रा संभव हो सकेगी।

- यह सेमी हाई-स्पीड रेलवे शहरों में सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को एक-दूसरे के करीब लाएगा।

निर्णय : 2030-31 तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक वस्त्र बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए 5,659.22 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'कपास उत्पादकता मिशन' को मंजूरी।

प्रभाव : यह मिशन भारत सरकार के 5-एफ यानी खेत से रेशा, रेशा से कारखाने, कारखाने से फैशन, फैशन से विदेश तक (फार्म टू फाइबर टू फैक्टरी टू फैशन टू फॉरेन) विजन के अनुरूप है।

- इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से मौजूदा और नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर प्रचार और उसे अपनाकर विस्तार करना है।
- साथ ही, उद्योग को कम से कम संदूषण वाली कपास की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना है। ■



12 वर्षीय संकल्प यात्रा

विकसित भारत की यात्रा का एक नवयुग



लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 2014 से 2026 एक ऐसे युग का पर्याय बन गया है जिसने संकल्पों की सिद्धि का नया अध्याय लिखा है। यह साक्षी बन गया है क्रांतिकारी परिवर्तनों का और आज देश का जन-जन इन परिवर्तनों में खुद को सहभागी महसूस कर पा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष की उपलब्धियां, तप-तपस्या से निकला वह अमृत है, जो अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध होकर कर चुका है नवनिर्माण की ओर प्रस्थान...



राष्ट्र की विकास यात्रा में एक समय ऐसा जरूर आता है जब देश स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करता है। नए संकल्प लेता है, सिद्धि का मार्ग ढूंढता है। दृढ़ इच्छाशक्ति से उसे साकार करने में जुट जाता है। यहीं से कुछ ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं, जो युगों-युगों तक जन-जन की स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वर्ष 2014 में देश की राजनीति ने करवट ली। देश ने एक ऐसी भोर देखी जहां से शुरू हुई विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है। विकसित भारत के एक विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे राष्ट्र के नवनिर्माण की इस यात्रा के 9 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारत की संस्कृति और अलग-अलग धर्म के शास्त्रों में 12 के अंक का एक विशेष महत्व भी है। शास्त्रों में 12 वर्ष की तपस्या का उद्देश्य साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म-साक्षात्कार में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 12 वर्ष की तपस्या एक कठोर और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है और हर कोई इसे करने में सक्षम नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष की विकास यात्रा केवल तात्कालिक समय की जरूरत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक-सुविचारित दृष्टिकोण पर आधारित रही है।

दरअसल, बीते 12 वर्षों में सेवा ही संकल्प और कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की सोच ने ही पुरानी धारणाओं को तोड़ विकास के नए पथ का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीते 12 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और सही अर्थों में आजादी का अहसास कराने की पहल हुई है, उसने पत्थर पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आजादी के अमृत काल से शुरू होकर स्वर्णिम वर्ष तक की यात्रा में नए भारत की नई तकदीर लिखने वाली है। एक ऐसा नया भारत जो युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान दे रहा है, नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, गरीबों के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई मिल रही है। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। बीते 12 वर्ष में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों के घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत तक की ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वह निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। पहले की तुलना में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह सफर यहीं



पूरा नहीं होता है। देश को पूर्णता तक जाना है। इसी संकल्प के साथ भारत ने अमृत काल की यात्रा प्रारंभ की है जहां शत-प्रतिशत गांवों में सड़कें हों, शत-प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत-प्रतिशत पात्र जरूरतमंद के पास आयुष्मान भारत कार्ड हो, शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो या आवास योजना हर उस व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ना है जो इसके हकदार हैं। पटरी और फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वालों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। देश आज हर घर नल से जल मिशन को लेकर तेजी से काम कर रहा है। सर्वांगीण-सर्वसमावेशी-सर्वस्पर्शी विकास की सोच से केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग न छूटे, कोई भू-भाग, देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। चाहे नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, किसान हो या गरीब-वंचित, सोच केवल एक ही है- विकास सर्वांगीण होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को भी आगे लाने के लिए पिछले 12 वर्षों में प्रयास किए गए हैं। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, आदिवासी अंचल, भविष्य में भारत की विकास यात्रा के बहुत बड़े आधार बन रहे हैं। इन सभी के लिए सुशासन का ऐसा मंत्र हो जो बहुमत की बजाए सर्वसम्मति की सोच को बढ़ावा देता है और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” जिसका ध्येय वाक्य बन चुका है। एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर राष्ट्र बढ़ रहा है जहां गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले।

विकसित भारत का मजबूत होता मार्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर कई मंचों पर ऐसे कामों की सूची गिना चुके हैं जो आजादी के शुरुआती वर्षों में ही हो जाने चाहिए थे। लेकिन उनके बारे में स्थायी समाधान की दीर्घकालिक सोच तब नहीं अपनाई गई। ऐसे में जो काम सात दशकों से लंबित या कहें कि अटके-लटके पड़े थे, उसे मौजूदा नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं। इससे उदीयमान नए भारत का निर्माण हो रहा है। बीते 12 वर्षों में भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना किया है, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण



तेज गति से विकास भी किया है। बीते 12 साल में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया गया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। उत्तर में देखें तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक, चिनाब ब्रिज बना है। पश्चिम में देखें तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी-ब्रिज, अटल सेतु बना है। पूर्व में देखें तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे। दक्षिण में देखें तो दुनिया के गिने-चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक, पंवन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। इसी तरह, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही हैं। इस विकास के पीछे एक सोच है- जब भारत का प्रत्येक क्षेत्र आपस में जुड़ता है तो विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग मजबूत होता है। नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण बना है। इस नए भवन में पहला बिल महिलाओं को संसद-विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के साथ पारित हुआ। इसी तरह 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की ओर बढ़ते भारत के कदम का परिचायक है। तीन तलाक, राम मंदिर, बोडो समझौता, अनुच्छेद 370 जैसे कई फैसलों से अमन-शांति स्थापित हुई। ऐसे फैसले जो दशकों से लंबित थे, जिन्हें स्थायी समस्या मान लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाधान निकला और नए भारत का अभ्युदय हो रहा है।

तकनीक से परिवर्तन का नया युग

भारत उन चंद देशों में शुमार है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी नीतियों को बनाने में सबसे आगे हैं। कई क्षेत्र जिनमें टेक्नोलॉजी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तकनीक से पारदर्शिता के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में शहरों से अधिक इंटरनेट डेटा की खपत हो रही है। कोविड काल में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को नई गति मिलने से डिजिटल लेनदेन को लोगों ने संस्कृति बना लिया। ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापक बाजार की उपलब्धता बढ़ी है। तकनीक की वजह से ही आज शत-प्रतिशत लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि एक रुपये में गांव तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। योजनाओं का क्रियान्वयन हो या निगरानी, तकनीक गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

को गति की शक्ति प्रदान कर रही है। आईटी-फेसलेस असेसमेंट जैसी सुविधाओं ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं तो ई-ऑफिस जैसी पहल ने प्रशासन की गति को तेज किया है। गांवों में पोस्टल बैंक, स्कूलों में अटल इनोवेशन मिशन से नई संस्कृति की शुरुआत हुई। एक समय भारत में नौकरी मांगने वाली सोच थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे बदलकर नौकरी देने वाला बनाया। स्टार्टअप और मुद्रा की सहूलियत से आज युवा नई उड़ान भर रहे हैं। भारत में पहले स्टार्टअप शब्द गिने-चुने लोग ही समझते थे, लेकिन आज गांव तक युवा इसे समझ रहा है और अब यूनीकॉर्न बनने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको-सिस्टम बन गया है।

वैश्विक नेतृत्व का अनुकूल अवसर

बीते 12 वर्षों में भारत का मान देश और दुनिया में बढ़ा है और भारत एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के संकट काल में ऑपरेशन गंगा, ग्लासगो में कॉप-26 और शर्म-अल-शेख में कॉप 27 की बैठक में विकासशील देशों की मुखर आवाज बनकर उभरा भारत, संयुक्त राष्ट्र, बिम्स्टेक, जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की तरफ दुनिया की निगाह, इसकी मिसाल है। जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को नई राह दिखाई है और विश्व को भारत की संस्कृति के साथ-साथ सामर्थ्य की भी अनुभूति कराई है। पर्यावरण के क्षेत्र में मिशन लाइफ और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल ने दुनिया को प्रकृति व वन्यजीवन के साथ समन्वय का मार्ग दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संकट की घड़ी में पड़ोसी और दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत पहला मददगार राष्ट्र बना है तो कोविड काल में दुनिया के लिए औषधि का केंद्र बना था। बीते 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वहीं देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर ऐसा माहौल बना है कि आम नागरिक केंद्र सरकार की योजनाओं में सहभागी बनकर विकास का भागीदार बन गया है।

निश्चित रूप से युगदृष्टा और साहसिक सुधारवाद के प्रणेता के तौर पर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नए विश्वास के साथ नई शुरुआत' के प्रतीक बन चुके हैं। एक सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण की पहल 'नया भारत, विकसित भारत' का विजन है। बीते 12 वर्ष में केंद्र सरकार के संकल्पों को आज प्रत्येक भारतवासी साकार होते देख रहा है।

आइये, संकल्प से सिद्धि की 12 वर्षीय यात्रा की इन उपलब्धियों को आगे के पांच खंडों में जानते हैं...



आवरण कथा
विकास यात्रा के
12 वर्ष

लोक सेवा ही ध्येय

“जो मुझे जानते हैं, वो मुझे समझते भी हैं। मैं अपने लिए नहीं, न ही अपनों के लिए हूँ। मैं यहां गरीबों के लिए हूँ। मैं गरीबी में जन्मा हूँ और गरीबी को जिया भी हूँ। मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि वे एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति के दिल से निकली आवाज है, जिनके मन में देश के दलित, गरीब, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए अपार संवेदनशीलता है। हर निर्णय करते समय हमेशा अंत्योदय और गरीब कल्याण के लिए सबसे पहले सोचना उनकी प्रकृति बन गई है। राष्ट्र की हर सोच, भारत की संस्कृति और संस्कार, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ विकसित भारत के सुनहरे सपने को समर्पित है। इस दृष्टिकोण ने ही बीते 12 वर्ष में देश के किसान, गांव-गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के माध्यम से स्वास्थ्य की सुरक्षा दी है। इस वर्ग की आकांक्षाओं को मिले हैं नए पंख तो समावेशी विकास से सर्वांगीण सुरक्षा का एक चक्र बनाकर स्वावलंबी भारत की दिशा में बढ़ाया कदम...

गरीब कल्याण

आवरण कथा
विकास यात्रा के
12 वर्ष

गरीब कल्याण से गरिमामय जीवन

आज भारत में सरकार की उपलब्धियों की बात होती है तो उसमें गरीब कल्याण सर्वोपरि होता है। केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में गरीब कल्याण को अपना ध्येय बनाया है, जहां तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण आधार है। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में व्यक्त 'गरीब कल्याण' के संकल्पों को साकार करने वाली अनेक योजनाओं से गांव और गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। दुनिया की विश्वसनीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के हर निर्णय में, अंत्योदय के साथ गरीब कल्याण और सशक्तीकरण बन गई है स्थायी सोच...

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना



81

करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है मुफ्त अनाज।

5

वर्षों के लिए बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी, 2024 से।

- मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सफलतापूर्वक की गई, कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदला गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देशभर में शत-प्रतिशत राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया गया।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना लागू की गई। 207 करोड़ से अधिक पोर्टिबिलिटी लेनदेन मार्च, 2026 तक दर्ज किए गए हैं।

25

करोड़ देशवासी पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबी को हराकर बाहर निकले हैं। उनके तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने का अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है।

19%

थी देश में 2015 में सोशल सिक्योरिटी, 2025 में 64.3% पहुंची। 94 करोड़ से अधिक लोगों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है।

12

करोड़ शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं, जिससे देश खुले में शौच से मुक्त हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में एक बड़ी प्रगति हुई है।



वित्तीय सुरक्षा

58.12

करोड़ प्रधानमंत्री जन-धन खाते खोले गए 15 अप्रैल, 2026 तक। इन खातों में करीब 2.94 करोड़ रुपये की राशि है जमा।



32.21

करोड़ (55.8%) जन-धन खाते महिलाओं के हैं और लगभग 45.17 करोड़ (78.2%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।



2 लाख रुपये



का जीवन बीमा कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु पर। योजना में 27.33 करोड़ से अधिक नामांकन।

- दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। 57.92 करोड़ नामांकन हुए।



9 करोड़

से अधिक नामांकन अटल पेंशन योजना में हुए।

- स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को विनिर्माण, व्यापार, सेवा एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 62,790 करोड़ रुपये की राशि के ऋण 2.75 लाख लोन स्वीकृत।
- जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिशक्ति ने एक मजबूत वित्तीय समावेशन मंच तैयार किया है, जिसमें जन-धन खाते को मोबाइल नंबर और आधार से जोड़ा जाता है।
- पीएम स्वनिधि योजना - शुरुआत से 15 अप्रैल, 2026 तक 74.90 करोड़ स्ट्रीट वेंडर को लोन दिए गए।

जल जीवन मिशन

12.61 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए, 13 मई, 2026 तक।

3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास 2019 में मिशन के आरंभ के समय नल का कनेक्शन था।

15.85 करोड़ परिवारों को 13 मई, 2026 को मिल रहा है घर में नल से जल, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से।

- 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी।



“

मुझे कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं होती बल्कि मेहनत से गरीब जनता के चेहरे पर आई मुस्कान अत्यंत संतोष की अनुभूति करवाती है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एक नए युग की शुरुआत

दशकों तक उपेक्षित रहा भारत का किसान यानी अन्नदाता अब भारत की विकास यात्रा का सहभागी बन चुका है। किसानों के प्रति सोच का ही परिणाम था कि कृषि मंत्रालय का नाम अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो चुका है। अपनी इसी सोच से बीते 12 वर्षों में समग्रता के साथ किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद के चरणों में उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती आ रही है, जिससे किसानों को मिली है नई दिशा...

बढ़ रहा खाद्यान्न का उत्पादन

357.73

मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा रिकार्ड खाद्यान्न का उत्पादन कृषि वर्ष 2024-2025 में भारत ने किया।

150

मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।



- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बना है। ये ब्लू इकॉनमी में देश की सफलता को दिखाता है।



- दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी, भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। ये सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है।



पीएम किसान सम्मान निधि

इस योजना में, किसानों के आधार सीड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किश्तों में हस्तांतरित की जाती है। प्रारंभ से अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों को 22 किश्तों में 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए हैं।



सरकार लगातार बढ़ा रही है एमएसपी

- 2018-19 से सरकार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा रही है। यह किसानों की फसल की लागत से कम से कम 1.5 गुना की जाती है, ताकि किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ मिल सके।



कृषि विकास के लिए निधि

वर्ष 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए 1,32,561 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया। एग्री-एजुकेशन और अनुसंधान के लिए लगभग 9,967 करोड़ रुपये रखे गए। यह कृषि विकास को निरंतर प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

24.96

करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 6 फरवरी, 2026 तक पंजीकृत हैं।

60

वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। इसमें प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है।



आज केंद्र में जो सरकार है, वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बंटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

किसानों को रियायती दर पर मिलती रही खाद

कोरोना और उसके बाद जो युद्ध हुए, उसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें कई गुणा बढ़ गईं। विदेशी बाजारों में खाद मिलनी भी मुश्किल हो गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की।

3,000

रुपये में यूरिया की जो बोरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलती है, वही बोरी केंद्र सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत पर दे रही है।



- 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च इस पर सरकार ने अपने खजाने से किए हैं, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े।
- बीते 12 वर्षों में देश के किसान के इर्द-गिर्द केंद्र सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बुना है। **MSP**, सस्ता ऋण, फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी हैं।
- किसानों की खेती नई तकनीक से जुड़े, उन्हें सिंचाई के नए तरीकों से जोड़ा जाए और फसलों को भी लाभ मिले, इस मंशा से सरकार ने **Per Drop More Crop** की नीति बनाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो-इरिगेशन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया।
- केंद्र ने कुसुम योजना बनाई। आज बहुत सारे किसान, न सिर्फ सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर रहे हैं बल्कि उससे बिजली बनाकर, पैसे भी कमा रहे हैं।



मध्यम वर्ग

आवरण कथा
विकास यात्रा के
12 वर्ष

मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान

बहुत तेजी से बदलते भारत में विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक तिहाई आबादी वाला मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है, जिनकी आकांक्षाओं को केंद्र सरकार की ओर से बीते 12 वर्षों में मिले हैं नए पंख...

आयकर से मिली राहत

₹12 लाख

तक की वार्षिक आय पर नई कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं।

₹75,000

की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये की सीमा।

- केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव।
- स्लैब दरों में कटौती एवं छूट से मध्यम वर्ग को व्यापक कर राहत, जिससे घरेलू उपभोग व्यय एवं निवेश को मजबूती मिलेगी।
- आयकर दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ पर पहुंची।

उड़ान योजना

1.64

करोड़ से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना का लाभ 3.45 लाख फ्लाइट सेवा से लिया है।

केंद्र सरकार ने इस योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

665

रूट से 95 एयरपोर्ट-हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम कनेक्टेड हैं।

- आने वाले वर्षों में इसके तहत, छोटे-छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है।
- साल 2014 से पहले, देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में हैं।

वंदे भारत सेवा

9.1 करोड़ यात्रा वंदे भारत सेवा की शुरुआत से 31 मार्च, 2026 तक कर चुके हैं 1 लाख ट्रिप में यात्रा।

162 वंदे भारत सेवा अब तक शुरू की जा चुकी है, जिससे कई कॉरिडोर पर यात्रा का समय 45% तक कम हो गया है।

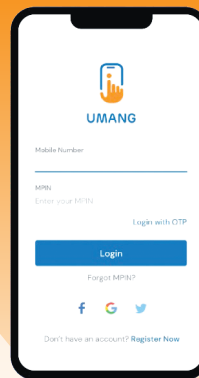
90 सेवाएं 8-कोच वाली | 38 सेवाएं 20-कोच वाली | 34 सेवाएं 16-कोच वाली

गरीब

तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रही है।



उमंग एप : प्लेटफॉर्म एक, सेवाएं अनेक



11.02 करोड़ रजिस्ट्रेशन उमंग एप पर।

766.35 करोड़ ट्रांजैक्शन।

2,517 सर्विस ऑनबोर्ड।

2017 में लॉन्च किए गए इस एप का मतलब है मध्यम वर्ग के लिए कम कतारें, ज्यादा नियंत्रण और सार्वजनिक सेवाओं तक जल्दी पहुंच।

डिजिटलॉकर



63.88 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता।

950 करोड़+ दस्तावेज जारी।



मोबाइल डाटा का खर्च हुआ कम

97% मोबाइल डाटा पर खर्च कम हुआ 2014 के मुकाबले 2025-26 में।

रियल एस्टेट विनियमन

■ घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए, संसद ने 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम पारित किया।

■ 1.57 लाख केस रेरा ने निपटाए हैं, 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में रेरा अथोरिटी है।

■ 1.61 लाख से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 1.13 लाख रियल एस्टेट एजेंट देशभर में रेरा के तहत पंजीकृत हैं।



पीएम आवास योजना-शहरी

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई- यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। ताकि देश भर में पात्र कामकाजी पेशेवर शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें।

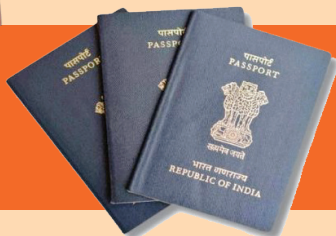
हृ कि **125.15** लाख घरों को अब तक देशभर में मंजूरी दी गई है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.67 लाख घर शामिल हैं।



116.57 लाख मकानों का निर्माण कार्य स्वीकृत मकानों में से शुरू हो चुका है, जिनमें से 97.30 लाख मकान 2 मार्च 2026 तक लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं।

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र

23 सर्किलों में 452 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू।



पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

36.88

लाख घरों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर सिस्टम लगाए गए 30 अप्रैल, 2026 तक।



19,480

करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी।

योजना में स्थापित क्षमता 10.77 गीगावाट तक पहुंची।

तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

बीते 12 वर्षों में, देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है।



मध्यम वर्गीय परिवार देश के लिए बहुत देता है तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की अपेक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। मैंने सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ईकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हों।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वास्थ्य समृद्धि की ओर भारत

क्या आप जानते हैं कि जीवन जीने की औसत आयु में 1 साल की बढ़ोतरी, देश की जीडीपी में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर देती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेक्टर को आजाद भारत में पहली बार 2014 से न केवल प्राथमिकता मिली, बल्कि मौजूदा केंद्र सरकार ने इसे नीतिगत और राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा कर स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित कर बीते 12 वर्षों में भारत सरकार ने बेहतर परिणामों की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का कर रहा नेतृत्व...

स्वास्थ्य शिक्षा में 12 वर्ष में दिखे बदलाव

23

एम्स, 2014 में यह संख्या 7 थी।

172%

तक बढ़ीं 12 वर्ष में मेडिकल सीटें

818

हुई एलोपैथी मेडिकल कॉलेज की संख्या, 2014 में 387 थी।

323

दंत चिकित्सा और 942 आयुष संस्थान।



1,28,975

पहुंची 51,384 से बढ़कर एमबीबीएस सीटों की संख्या।

85,020

पहुंची 31,185 से बढ़कर मेडिकल पीजी की सीटों की संख्या।

टीकाकरण

12

तरह की बीमारियों से बचाव के लिए नवजात, बच्चों और किशोरों को टीके लगाए जाते हैं।

- वर्ष 2015 में शुरु मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के तहत उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है।
- प्रति वर्ष 2.9 करोड़ गर्भवती और 2.54 करोड़ नवजात का निःशुल्क टीकाकरण।
- वर्ष 2026 में सर्वाधिकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लॉन्च।
- पूर्ण टीकाकरण: वर्ष 2015 में 62% था जो बढ़कर जनवरी 2026 में 98.4% हो गया।
- कोविड-19 के दौरान भारत ने 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी।





मिले बेहतर परिणाम

- 1990 से मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में 86 प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक औसत 48 प्रतिशत से अधिक है।
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो वैश्विक औसत 61 प्रतिशत से अधिक है।
- नवजात मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 54 प्रतिशत है।
- शिशु मृत्यु दर में पिछले दशक में 37 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जो 2013 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 40 मौतों से घटकर 2023 में 25 हो गई है।



संस्थागत प्रसव	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी	
	वर्ष 2017-18	वर्ष 2025	वर्ष 2017-18	वर्ष 2025
	90.5%	95.6%	96.1%	97.8%

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय)

- 23 सितंबर, 2018 को (एबी-पीएमजेवाई) शुरू की गई। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज।

12 करोड़ से अधिक को मिला इलाज।

36,038 अस्पताल योजना में पंजीकृत।

43.93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने।



आयुष्मान आरोग्य मंदिर

1,84,235 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (27 फरवरी 2026 तक) कार्यरत हैं।

42.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को (31 दिसंबर 2025) तक टेली-परामर्श दिया गया।





मेडिकल टूरिज्म

- वर्ष 2025 में 5,07,244 विदेशी नागरिक विशेष रूप से चिकित्सा उपचार के लिए पहुंचेंगे।
- वर्ष 2030 तक मेडिकल टूरिज्म का बाजार बढ़कर 16.2 अरब डॉलर होने का अनुमान।
- ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा सुविधाओं को 172 देशों तक बढ़ाया गया।

चिकित्सा पर्यटन सूचकांक वर्ष 2020-21 के अनुसार...

- भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 46 चिकित्सा पर्यटन स्थलों में 10वें स्थान पर।
- दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस पर्यटन बाजारों में 12वें स्थान पर।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर।

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई

19,200

जन औषधि केंद्रों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध।

- इन केंद्रों पर 2,100 से अधिक दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा उत्पाद उपलब्ध हैं, जो बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर बेचे जाते हैं।



लगभग 40,000

करोड़ रुपये की बचत आम लोगों को सस्ती दवा मिलने की वजह से हुई है।

जेब पर बोझ हुआ कम

- स्वास्थ्य उपचार पर अपनी जेब से होने वाला खर्च वर्ष 2014-15 में 62.6% घटकर वर्ष 2020-21 में 39.4% हो गया है। इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बहुत बड़ा योगदान है।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा नीति के जरिए श्रेष्ठतम स्वास्थ्य हासिल करना तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई के बिना उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

सुखद

- 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित।
- 2015 में नवजात शिशुओं में होने वाले टिटनेस का उन्मूलन।
- 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया।
- भारत निकट भविष्य में कालाजार के उन्मूलन की दिशा में भी अग्रसर है।





सशक्तीकरण की अविरल यात्रा

हर पल विकास, हर पल नई संभावनाएं

स्वर्णिम पथ पर बढ़ने से पहले जरूरी था कि उन वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिन्हें कोई पूछता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वर्गों को न केवल पूछा, बल्कि उसे पूजा। वंचितों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं-नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: नारी के नेतृत्व में विकास का मंत्र बना और बीते 12 वर्ष में नारी शक्ति हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। इसी तरह यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है... युवा पीढ़ी को समर्पित विकसित भारत का यह मंत्र इस बात का द्योतक है कि भारत का युवा अपनी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने को तैयार है। आज युवा शक्ति के सामर्थ्य को नई पहचान मिली है तो भारत के ज्ञान-विज्ञान और कालजयी उपलब्धि का प्रतीक बन गई है नए भारत की अमृत पीढ़ी। आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 12 वर्ष एक युग के रूप में वंचितों, नारी शक्ति, युवा शक्ति और किसानों के सशक्तीकरण का कालखंड बन गया है। नए भारत के नए नेतृत्व ने संवेदनशील सोच और समावेशी दृष्टिकोण के साथ इस दौरान सभी वर्गों-क्षेत्रों को विकास का सहभागी बनाया और फिर शुरू हुई स्वर्णिम भारत की यात्रा...

नारी सशक्तीकरण

आवरण कथा
विकास यात्रा के
12 वर्ष

नारी सशक्तीकरण और नया भारत

नारी तू नारायणी, तुमसे ही सामर्थ्य है, तुम्ही हो राष्ट्रशक्ति। इसी संकल्प के साथ नया भारत उत्कृष्टता के नित नए अध्याय लिख रहा है। महिला शक्ति के बिना किसी राष्ट्र की समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में केवल नारी उत्थान नहीं, बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास की दृष्टि बीते 12 वर्षों में राष्ट्र की नीति का महत्वपूर्ण आधार बनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और नेतृत्व के अवसरों में महिलाओं को सशक्त करने की अनेक पहलें इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। अब लोकसभा-विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध...

महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम

2023 में नई संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया गया।

14 लाख से अधिक महिलाएं आज भारत में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब-करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।



■ बीते 12 साल में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 'पीएम आवास योजना' के तहत घर की मालकिन बनी हैं।
■ आज 70% से अधिक पीएम आवास अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम पर हैं।

■ स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 75% कर्ज महिलाओं को दिए गए हैं। इसके अलावा जन धन खातों में 55% हिस्सेदारी महिलाओं की है।

70% लोन मुद्रा योजना में महिलाओं को मिले हैं।

- 26 हफ्ते कर दिया गया महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव।
- 10 करोड़ महिलाएं बीते 12 वर्ष में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
- 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रखा है। इसमें से 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
- सितंबर 2025 में चलाए गए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत लगभग सात करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हुई।



■ 2015 में सरकार ने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया जिसका लक्ष्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।

■ मिशन शक्ति पोर्टल: जनवरी 2025 में मिशन शक्ति पोर्टल (<https://missionshakti.wcd.gov.in/>) का शुभारंभ, 23 मार्च 2026 तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2,428 संरक्षण अधिकारियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट।

सशक्त होती महिलाएं

48% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक।

- भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता है। इसी प्रकार ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, यानी NDA में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है।

महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात

22% 39%

2017-18 2025



तक पहुंच गई है मैथ्स और साइंस की पढ़ाई यानी STEM Education में बेटियों की संख्या।

पीएच.डी. में महिला शोधार्थियों का नामांकन 135.6% की असाधारण वृद्धि (2014-15 से 2022-23 तक) के साथ दोगुना से अधिक बढ़ गया, जिससे 64,724 अतिरिक्त महिला शोधकर्ता जुड़ी।



खुशहाली की ज्योति : उज्ज्वला योजना

10.57 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 मार्च, 2026 तक दिए गए।

2 से 3 घंटे प्रतिदिन बच जाते हैं महिलाओं के, जो पहले उन्हें चूल्हा जलाने के संसाधन एकत्रित करने में लगते थे। अब महिलाएं इस समय का उपयोग आय-अर्जित करने की गतिविधियों या परिवार की देखभाल के लिए करती हैं।



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना

22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना का एक दशक पूरा।

जन्म के समय राष्ट्रीय स्तर पर लिंग अनुपात (प्रति 1,000 लड़कियां)



918

2014-15

929

2024-25

सेकेंडरी स्तर पर स्कूलों में लड़कियों के कुल दाखिले का अनुपात

2014-15

75.51%

2024-25

80.2%



प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

8,812

पंजीकृत स्वेच्छाकर्मी

22,349

पीएमएसएमए सेवाएं प्रदान करने वाली सुविधाओं की संख्या

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

यह सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये (साथ ही जननी सुरक्षा योजना प्रोत्साहन, औसतन 6,000 रुपये) और दूसरे बच्चे (यदि लड़की हो) के लिए 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करती है।



4.28

करोड़ महिला को मिला लाभ।

4.92

करोड़ महिला पंजीकृत।

20,150 करोड़

कुल राशि का भुगतान।

सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं का सशक्तीकरण

- 22 जनवरी 2015 को सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई जिसका ब्याज दर 8.2% है।
- 4.6 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं शुरुआत से अब तक और कुल जमा राशि 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।



आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। मुझे संतोष है कि 2014 में, आप सब देशवासियों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और तब से लेकर अब तक, हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

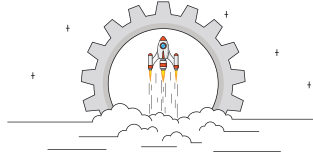
भारत का परचम लहराने वाले सारथी

यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है... युवा पीढ़ी को समर्पित विकसित भारत का यह मंत्र इस बात का द्योतक है कि भारत का युवा अपनी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने को तैयार है। यही कालखंड है जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसलिए बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार की दूरदृष्टि से युवा शक्ति के सामर्थ्य को नई पहचान मिली है और भारत के ज्ञान-विज्ञान और कालजयी उपलब्धि का प्रतीक बन गई है नए भारत की अमृत पीढ़ी...

स्टार्टअप

2.23 से अधिक स्टार्टअप, 23.36 लाख से अधिक नौकरियों का हुआ सृजन। फंडिंग, क्रेडिट सहायता लाख और सार्वजनिक खरीद में देखी गई मजबूत वृद्धि।

- 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिर्कॉर्न थे, आज भारत में 127 एक्टिव यूनिर्कॉर्न हैं।



55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जो इस पहल की शुरुआत के बाद से एक वर्ष में सबसे अधिक।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

57.79

- करोड़ लोन में 40.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया पीएमएमवाई में 11 वर्ष के दौरान। इससे लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण इकोसिस्टम मजबूत हुआ।



- मुद्रा योजना गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये तक के बिना गारंटी वाले संस्थागत ऋण तक निर्बाध पहुंच को सुगम बनाती है।



शिक्षा संस्थानों की बढ़ी संख्या

2014 से लेकर अब तक

- 16 से बढ़कर 23 हुई आईआईटी की संख्या।
- 13 से बढ़कर 21 हुई आईआईएम की संख्या।



23 हुई 7 से बढ़कर एम्स की संख्या।

- 387 से बढ़कर 818 हुई मेडिकल कॉलेजों की संख्या।
- 2 अंतरराष्ट्रीय परिसर आईआईटी के जंजीबार और आबुधाबी में।

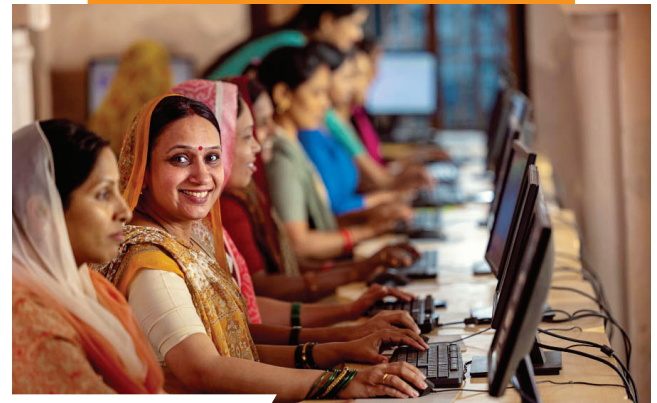
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

35

से अधिक क्षेत्रों में कुल 1.64 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत।

3,15,014

उम्मीदवारों को निर्माण, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों और करियर एवं शिक्षा परामर्शदाता पदों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।





12 वर्षों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी लगन से काम

12

लाख से अधिक नौकरियां रोजगार मेलों के माध्यम से मिली।



10,000

से अधिक अटल टिकरिंग लैब विद्यालयों में स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे 1.1 करोड़ से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं।

- 3 दशकों के बाद लागू हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
- भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं।
- नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 9 से 12 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव (एनवाईएफ) 2026 का आयोजन।
- पीएम श्री (उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल) - एनईपी-मॉडल संस्थानों के रूप में आधुनिक बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
- 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई। यह करीब साढ़े तीन करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी।

“

भारत के युवाओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को आगे बढ़ाया है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

खेलो इंडिया

27,500 से ज्यादा एथलीट ले रहे हैं खेलो इंडिया केंद्रों पर प्रशिक्षण।



8 गुना हुआ खेलो इंडिया बजट

118 करोड़ रुपये

924 करोड़ रुपये

2016-17 2026-27

अग्निपथ योजना

- 15 जून, 2022 को सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की। इस योजना के तहत, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को तीनों सेनाओं में 'अधिकारी रैंक से नीचे' के कैडर में चार साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है।

17.5

से 21 साल के युवाओं को चार साल की सैन्य सेवा के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य।

46,000

के पहले बैच ने 2023 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और तकनीकी कौशल के साथ-साथ सेवा निधि पैकेज और सेवा के बाद रोजगार में प्राथमिकता मिली।



वंचितों को वरीयता, सुशासन की पहचान

आज देश में समान भाव से काम हो रहा है जिससे बीते 12 वर्षों में लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। 2014 से पहले, समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही वंचितों को वरीयता का सिद्धांत अपनाकर बढ़ना शुरू किया। पहली बार कोई सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची, जिन्हें दशकों तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। पीएम मोदी कहते हैं जिन तक कोई नहीं पहुंचा, मोदी उन्हें पूजता है। गरिमामय जीवन स्तर मिलने से वे लोग भी राष्ट्र के विकास में दे रहे हैं योगदान...

आदिवासी विरासत को बढ़ावा



728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 428 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, 249 निर्माणाधीन हैं और 46 पूर्व-निर्माण चरण में हैं।

- वर्ष 2021 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस घोषित।

11

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी। अब तक 4 संग्रहालय 3 राज्यों में स्थापित। जिनमें झारखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 1 और मध्य प्रदेश में 2 संग्रहालय। शेष 7 पर काम जारी।

वंचितों के मिल रहा सुविधाओं का लाभ

- 13 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार जनकल्याण (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया। यह पोर्टल वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक।



1.15

करोड़ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को लाभान्वित करने का है पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य। 74.90 लाख लाभार्थियों को मिल चुका है लोन। 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाया गया ऋण वितरण अवधि।

- 60 करोड़ से अधिक लोगों के जीवनस्तर को ठोस नीतियों से ऊपर उठाने और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम भी हुआ।
- 31.65 करोड़ से अधिक ई-श्रम कार्ड जारी किए गए। इसमें अब तक 14 सामाजिक योजनाएं शामिल।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।
- वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन से पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- वित्त वर्ष 2025-26 में 75 लाख से अधिक अनुसूचित जाति लाभार्थियों को 7,981.47 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा।



प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

देश भर में 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। सभी राज्यों ने 31 मार्च 2019 से पहले विन्हित सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों के घर 100% विद्युतीकृत किए गए।

श्रम संहिता

चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को 21 नवंबर, 2025 से लागू करने की घोषणा। इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया गया।



प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की उपलब्धियां लगभग 30 लाख कारीगर और शिल्पकार पंजीकृत।

4,78,020

लोगों को 41,188 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत।

26,36,865

कारिगरों की बेसिक ट्रेनिंग और स्किल वेरिफिकेशन भी पूरा हुआ।

23,69,249

ई-वाउचर जारी किए गए।

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी (विकसित भारत जी राम जी) अधिनियम, 2025

- इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी, जो पहले 100 दिन की थी।



“

मेरे लिए तो जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब वीआईपी है। देश की हर माता-बहन-बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान वीआईपी है। देश का हर युवा वीआईपी है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आत्मनिर्भर भारत का आधार

आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर भारत का मूल आधार है। श्रीअन्न को दुनिया में स्थान दिलाना हो या किसानों को लागत से डेढ़ गुनी कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना हो या फिर किसानों की आय दोगुनी करना, यह वादा नहीं, सरकार का संकल्प है। बीते 12 वर्षों में कृषि को उद्योग की तरह विकसित करने की नीति और पहल ने किसानों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग बनाया है। ऐसे क्षेत्र जिसके लिए हम आयात पर निर्भर थे, उसकी पहचान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है, ताकि किसान हो सशक्त, राष्ट्र हो समृद्ध...

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)

1,656

मंडियों का एकीकरण
मार्च 2026 तक 23 राज्यों
और 4 केंद्र शासित प्रदेशों
में किया गया।

साथ ही

1.80 करोड़

से अधिक किसान, 2.73 लाख
व्यापारी और 4,724 किसान-
उत्पादक संगठन ईएनएएम
प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए।

- 2016 से मार्च 2026 के बीच 13.25 करोड़ मीट्रिक टन का व्यापार दर्ज किया गया, जिसका कुल मूल्य 4.84 लाख करोड़ रुपये था।
- व्यापार मूल्य 2024 में 3.19 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026 में 4.84 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो बढ़ते पैमाने और गहन बाजार जुड़ाव को दर्शाता है।
- मार्च 2026 तक, 204.76 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ, जो निरंतर परिचालन गति को दर्शाता है।
- ई-एनएएम एप के जरिए मोबाइल-आधारित मूल्य सूचना सेवाओं के तहत 247 वस्तुओं को शामिल किया गया है।



श्रीअन्न : 2018 में मिलेट्स (श्री अन्न) के महत्व को बताते हुए पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा, जिसने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया।

- वर्ष 2024-25 में लगभग 18.59 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इससे मिलेट्स उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें प्रमुख योगदान राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक का रहा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी एम के एम वाई)

इसके अंतर्गत 2 फरवरी 2026 तक 24.95 लाख किसानों का नामांकन किया जा चुका है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।



फसल बीमा संरक्षण

- 4.19 करोड़ किसानों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया, जिसमें 6.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।
- 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान वर्ष 2016-17 से मार्च, 2026 तक किया जा चुका है। 86 करोड़ से अधिक आवेदन इस अवधि में फसल बीमा के आए हैं।
- वर्ष 2022-23 की तुलना में कवरेज में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे जलवायु और बाजार से संबंधित जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा को और सुदृढ़ किया गया है।





दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत

■ देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत की।

■ पहली- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी- दलहन आत्मनिर्भरता मिशन।



24,000

 करोड़ रुपये

का बजट प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए जबकि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 1,440 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

■ इन योजनाओं पर सरकार करीब 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने वाली है। यह दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी।



किसान क्रेडिट कार्ड

10

 लाख करोड़ रुपये

से अधिक राशि 31 दिसंबर 2025 तक 7.57 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी गई।

■ किसानों को खेती और पशुपालन जैसी जरूरतों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल रहा है।

1.55

 करोड़

रुपे केसीसी कार्ड 31 जनवरी 2026 तक सहकारी समितियों के सदस्यों को जारी किए जा चुके हैं।

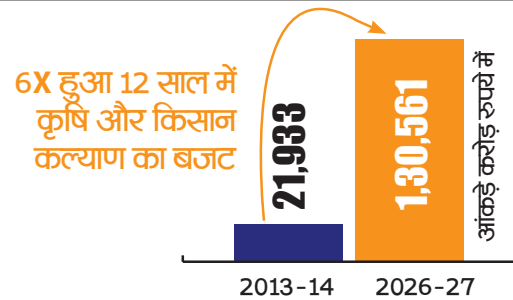


12 साल की उपलब्धियां

- बीते 12 वर्षों में, भारत का कृषि निर्यात करीब दो गुना हो गया, करीब-करीब 900 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ गया।
- फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर वन है।
- दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में दोगुना। अंडे का उत्पादन भी बीते 12 वर्षों में दो गुना हो गया है।
- इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं।
- 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है।
- पीएम फसल बीमा योजना से करीब दो लाख करोड़ रुपये वलेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
- 12 साल में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पाद संघ- FPO's बने हैं।

वैश्विक कृषि बाजार में भारत

- कृषि निर्यात से होने वाली आय वित्त वर्ष 2020 में 34.5 अरब डॉलर थी वहीं वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 51.1 अरब डॉलर हो गई।
- वित्त वर्ष 2025 में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित कृषि-खाद्य निर्यात 49.43 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो कुल निर्यात का लगभग 11.2% है।



“

आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख-दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



आवरण कथा
विकास यात्रा के
12 वर्ष

राष्ट्र निर्माण

विकसित भारत का संकल्प ही 'राष्ट्रनीति'

अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि *size of the cake matters* यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों को मिलेगा। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा, स्वाभाविक रूप से देश की समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। यही समृद्धि हर परिवार की, हर व्यक्ति की आय और जीवन स्तर में भी परिवर्तन लाती है। यही आज भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा का आधार बना है। इसी तरह बुनियादी ढांचा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधारस्तंभ होता है। यह न केवल विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स की प्रतिस्पर्धा को सशक्त करता है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी सुदृढ़ बनाता है और आर्थिक विकास की गाथा को एक नई उड़ान देती है। इस विकास गाथा में जब विज्ञान-तकनीक जुड़ता है तो व्यापार की सुगमता जनविश्वास पैदा करती है, जीवन की सुगमता को बढ़ाती है। बीते 12 वर्ष की राष्ट्र निर्माण की यात्रा में अब अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर भी ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण इंजन बन चुका है। यानी समग्रता में विकास की सोच से सामाजिक विकास और आर्थिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाया है तो नीतिगत सुधारों ने राष्ट्र निर्माण का नया अध्याय लिख विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।



आर्थिक विकास

अर्थव्यवस्था की अमृत यात्रा

समग्रता में विकास की सोच से सामाजिक विकास और आर्थिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाया गया तो नीतिगत सुधारों ने आर्थिक विकास का नया अध्याय लिख दिया। अर्थव्यवस्था और आर्थिक विषयों को भी जन-जन से इस तरह जोड़ा कि प्रत्येक नागरिक स्वयं को सहभागी मानने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि कोई है जो उनकी भी चिंता करता है। कर सुधार हो या फिर अर्थव्यवस्था को दिशा देने की पहल, जीएसटी हो या टैक्सपेयर चार्टर- फेसलेस व्यवस्था, संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को दी है नई दिशा और शुरू हो चुकी है भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था की नई कहानी...



विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते

- भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाई छू रही है। विदेशी व्यापार यानी निर्यात में नित नए रिकॉर्ड बना रही है।
- आर्थिक विकास की तीव्र गति के पीछे सबसे बड़ा कारण बीते वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक स्तर पर भारतीय बाजार को विस्तार मिलना रहा है।

भारत ने 27 अप्रैल, 2026 को न्यूजीलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो बीते वर्षों में

38 विकसित देशों के साथ

भारत का नौवां समझौता है।

विकास की गति में मजबूती

भारत वर्ष 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।

2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

7.3

ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का है अनुमान।



- वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच मजबूत घरेलू मांग के चलते, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी जो 2024-25 की चौथी तिमाही के 7.4 प्रतिशत से अधिक है। यह दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में आए उछाल के कारण वास्तविक सकल मूल्य वर्धन में 8.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

- विश्व बैंक का अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था 2026-27 में लगभग 6.6% की दर से बढ़ेगी। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- आउटलुक 2026 के अनुसार भारत की विकास दर 6.5% का अनुमान है जबकि विकसित देशों के लिए 1.8%, विकासशील देश के लिए 3.9%, पूरी दुनिया के लिए 3.1% रखी गई है।
 - अमेरिका: 2.3% ■ जर्मनी: 0.8% ■ ब्रिटेन: 0.8%
 - चीन: 4.4% ■ ब्राजील: 1.9% रखा है।

आत्मनिर्भरता से बढ़ता निर्यात

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का माल और सेवा निर्यात रिकॉर्ड 860.09 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2014 में 479 अरब डॉलर था।

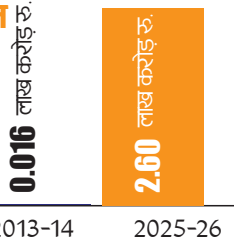


48 अरब डॉलर

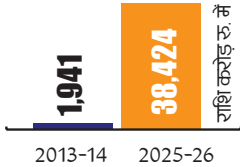
का हुआ 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात, 2014-15 में 6.3 अरब डॉलर निर्यात हुआ था। यह 20.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर है।

- 52.6 अरब डॉलर हुआ भारत का कृषि, बागान और समुद्री उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में जो 2013-14 में 39.6 अरब डॉलर था।

166 गुना हुआ मोबाइल फोन निर्यात



20 गुना हुआ रक्षा निर्यात



आर्थिक ताकत बढ़ाती एमएसएमई



7.47

करोड़ से ज्यादा एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार गतिविधियों जुड़ी हैं।

31.1%

है भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान।

48.58%

योगदान है देश के कुल निर्यात में।

35.4%

हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पादन में एमएसएमई का है।

32.8

करोड़ आबादी को आजीविका मुहैया कराती है एमएसएमई।

आंकड़े जो हैं मजबूती की पहचान

357.14

लाख करोड़ रुपये की जीडीपी वर्तमान मूल्य पर भारत का वित्त वर्ष 2025-26 में रहने का अनुमान।

484

लाख करोड़ रुपये के BSE मार्केट कैपिटलाइजेशन ने भारतीय शेयर बाजार की बढ़ती ताकत को दिखाया। (आंकड़ा 14 मई, 2026 का है।)

- 20.41 लाख करोड़ रुपये की बिक्री PLI योजना के तहत मार्च 2026 तक दर्ज की गई।
- 135.4 अरब डॉलर की रेमिटेस प्राप्त कर भारत 2025-26 में दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेस प्राप्त करने वाला देश बना।
- 1.89% (4.03 लाख करोड़ रुपये) रहा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए रेशियो दिसंबर 2025 में, मार्च, 2015 में 4.28% (3.23 लाख करोड़ रुपये) था। वर्तमान एनपीए कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर है।
- 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह 2025-26 में रहा, जो भारत की मजबूत कर व्यवस्था का प्रमाण है।
- 3.99 लाख करोड़ रुपये की राशि IBC के माध्यम से सितंबर 2025 तक कर्जदाताओं को वापस दिलाई गई।



701
अरब डॉलर



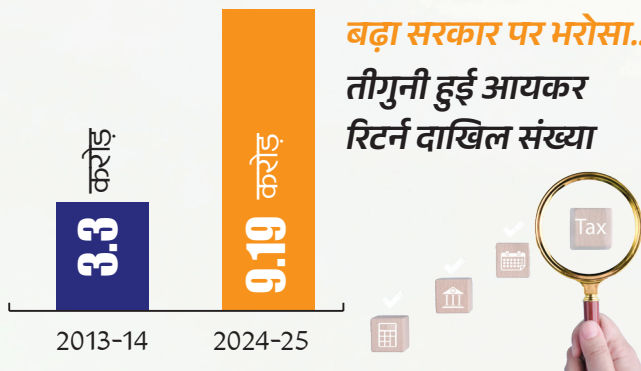
के करीब जनवरी, 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च, 2025 में 668.3 अरब डॉलर था।

अब अधिक खर्च के लिए बचेंगे पैसे

12.75 तक वेतनभोगी की सालाना आय पर नई कर व्यवस्था में अब नहीं देना होगा कोई आयकर।
लाख रुपये



बढ़ा सरकार पर भरोसा... तीगुनी हुई आयकर रिटर्न दाखिल संख्या



28 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2025-26 में।

- नेक्स्ट-जेन जीएसटी ने कराधान को सरल बनाया, करदाता आधार को 1.5 करोड़ तक विस्तारित किया जिसका नतीजा रहा है कि 2.36 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह अप्रैल 2025 में हुआ।

2.43

लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह अप्रैल 2026 में हुआ।



10.9%

तक भारत का कर राजस्व (जीडीपी के अनुपात में) पहुंचने का है 2026-27 का अनुमान। यह 2025-26 के संशोधित अनुमान 10.8% से थोड़ा अधिक है।

विकास और समृद्धि को बढ़ा रहे नए रोजगार

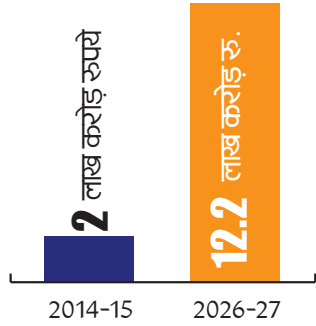
- भारत की घटती बेरोजगारी दर इसकी आर्थिक गति की मजबूती को दर्शाती है।
- 2025 का पीएलएफएस सर्वेक्षण बेरोजगारी में भारी गिरावट के साथ-साथ भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।
- नवंबर 2025 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 4.8 प्रतिशत रह गई, जो अक्टूबर 2025 में 5.4 प्रतिशत थी।
- यह अप्रैल 2025 (5.1 प्रतिशत) के बाद का सबसे निचला स्तर है।



भारत के आधार को मजबूत करता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

नए भारत का निर्माण साहसिक सुधार और अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर से ही संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास को केंद्र में रखते हुए जल, थल, नभ, प्रत्येक क्षेत्र में देश असाधारण स्पीड-स्केल के साथ काम कर रहा है। भारत के सौभाग्य की हस्तरेखाएं बनीं सैकड़ों ब्रिज, संसद भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि जैसी इमारतें, आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण बन गई है। अब अपने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की दहलीज पर खड़ा भारत, बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करते हुए विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मार्ग कर रहा है प्रशस्त...

इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 साल में 6 गुना बढ़ाया सरकार ने खर्च



आधुनिक भारत को मजबूती देंगे 2,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

41.5

लाख करोड़ रुपये

के 1,900 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर देश में चल रहा है मार्च, 2026 में काम। हर प्रोजेक्ट की लागत 150 करोड़ रुपये से अधिक।

- भारत सरकार पैमाना प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय क्षेत्र के इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है। इससे समय पर समीक्षा और डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद मिल रही है।
- देश भर में चल रहे इन इंफ्रा प्रोजेक्ट पर मार्च, 2026 तक करीब 20 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं, जो परियोजना की संशोधित लागत का लगभग 48.02 प्रतिशत है।

1,428

प्रोजेक्ट परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र (सबसे अधिक) से जुड़ी हैं जिन पर 22.66 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। यह बताता है कि देश कनेक्टिविटी-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दे रहा है।

777

प्रोजेक्ट की प्रगति 80% से अधिक हो चुकी है।

1,941

निर्माणाधीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 786 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

अब अटकती या लटकती नहीं हैं परियोजनाएं

- प्रगति यानी प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी जिसमें तकनीक की मदद से परियोजनाओं की निगरानी उनके नेतृत्व में की जा रही है।
- परियोजनाओं में होने वाली देरी में कमी आई और लागत वृद्धि को भी रोका गया है।

85

लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 382 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति के माध्यम से की गई। जहां रुकावटें थीं, उसे प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश से समयबद्ध दूर किया गया।





भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बढ़ा

91,287 किमी

मार्च, 2014

1,46,572 किमी

फरवरी, 2026

3,052 किमी हो गई है नियंत्रित राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर/एक्सप्रेसवे की लंबाई, 2014 में थी सिर्फ 93 किमी।

22,223 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फरवरी, 2026 तक भारतमाला कार्यक्रम में हुआ, 26,425 किमी को मंजूरी दी गई है।

समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

अधिसूचित राष्ट्रीय जलमार्ग

वर्ष 2014 में 5 थे जो वर्ष 2026 में 111 हो गए।

भारतीय ध्वज वाले जहाज/पोतों की संख्या

2014 में 1,250 थी, 2026 में 1,593 हो गई।

मेजर पोर्ट क्षमता करीब दोगुनी

वर्ष 2014 में 873 एमएमटीपीए थी, 2026 में 1,726 एमएमटीपीए हुई।



रेल हुई स्वच्छ, सुरक्षित और तेज

- नौ गुना हुई रेलवे को मिलने वाली बजट सहायता, 2014-15 में 32,000 करोड़ थी, 2025-26 में 2.78 लाख करोड़ रुपये मिला।

1,338 स्टेशन किए जा रहे हैं अमृत भारत स्टेशन योजना में पुनर्विकसित, 200 से अधिक का काम पूरा। 119 स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025-26 में किया।

139

टर्मिनल पीएम गति शक्ति के तहत चालू, 300 और स्थानों को नए टर्मिनल विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

162

वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू, 4,500 ट्रेन सेट का लक्ष्य। 2030 तक 800 ट्रेन चलेंगी।

- गुवाहाटी-हावड़ा (असम-पश्चिम बंगाल) मार्ग पर जनवरी, 2026 में वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के 260 ट्रेन सेट बनाने की योजना है।
- 51 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन के पूरा होने से मिजोरम अब भारत के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है।
- कश्मीर घाटी में रेल से माल ढुलाई और आर्थिक जुड़ाव मजबूत हुआ। 22 जनवरी 2026 को 42 डिब्बों वाली पहली पूरी मालगाड़ी, जिसमें 2,768 मीट्रिक टन चावल था, अनंतनाग पहुंची।
- 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर विकसित होंगे। लगभग 4,000 किमी नेटवर्क बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद।

“

आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। नॉर्थ में देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक, चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे, तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे, तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे। साउथ में दुनिया के गिने-चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक, पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



मेट्रो रेल नेटवर्क

1,155

किलोमीटर भारत का मेट्रो नेटवर्क 2026 में हो गया है जो वर्ष 2014 में भारत का मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था।



- केंद्रीय बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी कोष और नगर आर्थिक क्षेत्र जैसे नए उपाय पेश किए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास और संतुलित शहरी विकास को सुदृढ़ करते हैं।

- सरकारी परिसंपत्ति मौद्धीकरण से 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिससे नई परियोजनाओं में धन की फिर से आवाजाही हुई है। इसने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ी निजी भागीदारी

विश्व बैंक के अनुसार, भारत दक्षिण एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी (पीपीआई) निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है, जो इस क्षेत्र के कुल निवेश का 90% से अधिक है।



इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से बढ़ती हैं नौकरियां

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए हर करीब 8.3 करोड़ रुपये के निवेश से 7 से 30 नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसका सीधा फायदा स्टील, सीमेंट और परिवहन क्षेत्रों को होता है, जहां रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ते हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ एक साल में 12 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अनुमान बताता है कि सिर्फ निर्माण क्षेत्र से ही 2030 तक 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है।

बढ़ी ग्रामीण कनेक्टिविटी... प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



8.25

लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई शुरुआत से दिसंबर, 2025 तक।

7.87 लाख किलोमीटर सड़कें दिसंबर 2025 तक निर्मित हुईं

पीएम गति शक्ति ने दी इंफ्रा प्रोजेक्ट को गति

16.10

लाख करोड़ रुपये

की कुल अनुमानित लागत वाली 352 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने मूल्यांकन किया।

201 परियोजनाओं को मंजूरी दी, इनमें से 167 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।





विज्ञान और तकनीक

विज्ञान-तकनीक अर्थात् पारदर्शिता और परिवर्तन का युग

शास्त्रों में कहा गया है - ज्ञानम् विज्ञान सहितम् यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्।। अर्थात्, ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, विकास का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और तकनीक भारत के विकास का प्रमुख उपकरण बनकर लिख रहे हैं नए भारत की गाथा...

ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स में ऊंचाई छूता भारत

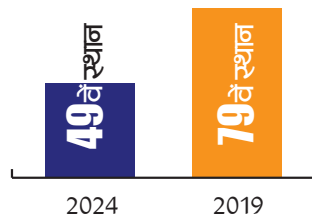
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025

भारत ने दुनिया की टॉप इनोवेटिव इकोनॉमी में 38वीं रैंक हासिल की।

WIPO रिपोर्ट 2023

भारत दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के मामले में छठे स्थान पर है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024



■ NRI दुनिया भर की 133 इकोनॉमी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और प्रभाव पर प्रमुख ग्लोबल इंडेक्स में से एक है।

■ रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।



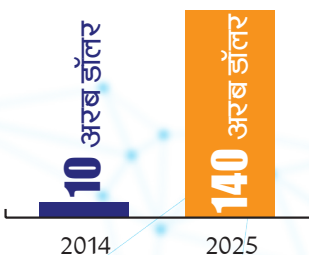
बीते एक दशक में बदलाव

- रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च दोगुना हुआ है।
- स्वीकृत पेटेंट संख्या 1 लाख के पार पहुंची, 2014 में 5,978 थे। पेटेंट की संख्या 17 गुना बढ़ी।
- 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।

6,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप हैं जो क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैटेरियल जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

- भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र भी अब उड़ान भर चुका है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी।

बायो-इकोनॉमी



राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

4 थीमैटिक हब स्थापित किए गए, जिनमें 43 संस्थानों के 152 शोधकर्ता और 17 परियोजना टीमें शामिल हैं।

- दुनिया का सबसे पहला और सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया।
- भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बीते वर्षों में चांद और मंगल तक पहुंचा है तो उस टेक्नोलॉजी के लाभ से किसान और मछुआरों को भी जोड़ा गया है।
- 5,000 से ज्यादा हुई सालाना महिलाओं की तरफ से पेटेंट फाइलिंग।
- **INSPIRE MANAK** ने देश भर में **STEM** शिक्षा को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2025-26 में स्कूलों से कुल 11.47 लाख विचारों और नवाचारों को जुटाया गया। नामांकन में से 52% लड़कियां।
- 43% हुई **STEM** एजुकेशन में महिला भागीदारी, वैश्विक औसत से अधिक।
- 10,000 टिकरिंग लैब्स बनाई गई, इनमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस सफलता के बाद अब 25 हजार नई अटल टिकरिंग लैब बनाने की दिशा में भारत काम कर रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में 7 नई **IIT's** और 16 ट्रिपल आईटी भी बन चुकी हैं।
- नई एजुकेशन पॉलिसी में युवा अब साइंस और इंजीनियरिंग जैसे **STEM** कोर्स अपनी स्थानीय भाषा में कर सकते हैं।
- आज रिटेल से लेकर लॉजिस्टिक्स तक कस्टमर सर्विस से लेकर बच्चों के होमवर्क तक, हर जगह **AI** का इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में भारत **इंडिया एआई मिशन** में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को जिस तरह से अपनाया है वैसे किसी और नेता ने नहीं किया है। राजनीति और नीति में उन्होंने जिस तरह से इसका उपयोग किया है उसके कई सबूत मिल चुके हैं।

भारत की डिजिटल ऊंचाई

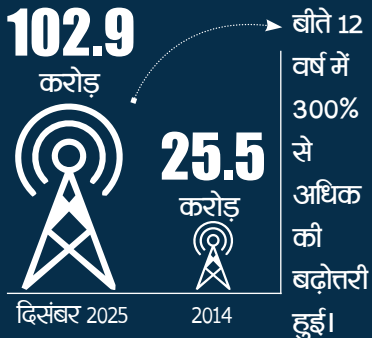
5जी सेवा केवल 22 महीनों में देश के 99.6% जिलों तक पहुंची, जो दुनिया के सबसे तेज रोलआउट में से एक है।

अब देश के **99.9%** जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं।

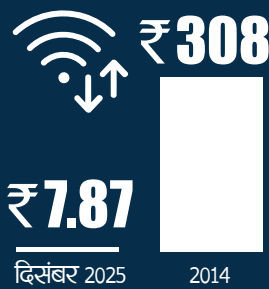
- 5G से भारत में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बड़े अवसर खुल रहे हैं। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, स्मार्ट सिटी, उद्योग और वित्तीय सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा।
- इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% की कमी आई है, जिससे आम लोगों के लिए इंटरनेट सस्ता और आसान हुआ।
- 6G तकनीक में दुनिया का अग्रणी देश बनेगा भारत, लक्ष्य है 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में लगभग 10% योगदान हो, अब तक भारत लगभग 4,000 पेटेंट दे चुका है।

7.22 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है भारतनेट योजना में, देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत हुई है।

भारत में इंटरनेट कनेक्शन संख्या



इतने रुपये में अब मिल रहा है 1GB डेटा



- 127.33 करोड़ हुए मोबाइल उपयोगकर्ता फरवरी 2026 तक। डिजिटल व्यवस्था के कारण पैसे भेजना, सामान खरीद में भुगतान करना आसान और तेज हुआ।
- मोबाइल त्रि-शक्ति से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सही लोगों तक पहुंच रहा है। डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी में आई कमी।

तकनीक ने वापस दिलाए चोरी हुए मोबाइल

10 लाख खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन भी वापस दिलाए गए हैं संचार साथी पहल से।



यह टेलीकॉम संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने का तकनीक आधारित समाधान है।

यहां संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले कॉल/मैसेज की शिकायत कर सकते हैं, मोबाइल चोरी रिपोर्ट और मोबाइल सेट असली या नकली है ये भी जांच सकते हैं।



2,300

करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी वाले लेनदेन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI) की मदद से मई, 2025 में शुरुआत के बाद से रोके गए।

जब साइंस को स्केल मिलती है, जब इनोवेशन, इनक्लूसिव बनती है, और जब टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो बड़ी उपलब्धियों की नींव मजबूत होती है, तैयार हो जाती है। पिछले 10-11 वर्षों में भारत की यात्रा इसी विजन का उदाहरण है। भारत अब टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बन चुका है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



जन विश्वास

सुधारों से आसान हुई उद्योगों की राह

भारत को बिजनेस और निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की कड़ी में भारत सरकार व्यापार सुधार कार्य योजना बनाकर व्यापक सुधारों की एक सीरीज पर लगातार काम कर रही है। इसमें श्रम, पर्यावरण, भूमि प्रशासन और कराधान सहित कई विषय शामिल हैं। सुधारों से देश में व्यवसाय स्थापित करने में लगने वाला समय और लागत दोनों में बड़ी कमी आई है। वर्तमान केंद्र सरकार चाहती है कि अनुकूल वातावरण से भारत में बढ़े नए निवेश, नए बिजनेस और नए रोजगार के अवसर...

भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के तहत कई बड़े सुधार कर रही है ताकि व्यापार करना आसान हो सके।

- बीआरएपी के 7 संस्करण में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 9,700 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं।
- श्रम, पर्यावरण, जमीन और टैक्स से जुड़े नियम सरल किए गए।
- पर्यावरण मंजूरी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और डिजिटल हुई।
- जमीन के उपयोग यानी लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन किया गया।
- उद्योगों के लिए जमीन की जानकारी जीआईएस और इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जोड़ी गई।
- बिल्डिंग बनाने के नियमों में बदलाव कर जमीन की बर्बादी कम की गई।
- बिल्डिंग की मंजूरी में थर्ड पार्टी यानी निजी एजेंसियों की मदद ली जा रही है।
- ऑक्यूपेशनल/कंप्लीशन सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन और आसान प्रक्रिया से मिलते हैं।
- कई कानूनों में छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया।
- 32 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सरकार और व्यापार के बीच सरल और डिजिटल अनुमोदन आसानी से हो सके।
- 3,000 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार से व्यापार के लिए जरूरी अनुमोदन तक पहुंच एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से आसान हुई है। केंद्रीय विभागों के 300 से अधिक अनुमोदन भी यहां जुड़े हैं।



विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल

भारत सरकार ने 2020 में विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल की शुरुआत की। इसमें 2025 तक केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने व्यवसायों और नागरिकों के लिए बोझ बने 47,000 अनुपालनों की पहचान कर उसे कम किया।

आरसीबी+ पहल के अंतर्गत, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले 23 अधिनियमों में पहचाने गए 6,262 अनुपालनों में से 4,846 अनुपालनों को कम किया है।

4,623

अनुपालनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।

4,270

अनावश्यक और दोहराव वाले अनुपालनों को समाप्त किया गया।

16,109

अनुपालनों को सरल बनाया गया।

1500

से अधिक पुराने कानून निरस्त किए गए।

विनियामक अनुपालन बोझ

22,287

अनुपालनों का डिजिटलीकरण किया गया।

सुधार पहल की शुरुआत जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 से हुई। इस विधेयक में 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया।

183 प्रावधानों को आपराधिक अपराध श्रेणी से हटाकर कारावास की सजा की जगह मौद्रिक दंड और अन्य प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्र लागू किए।



जन विश्वास अधिनियमों से आसान हुआ व्यापार

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों में शामिल 784 प्रावधानों को संशोधित किया गया।



- **317** प्रावधानों को जुर्माने से सिविल पेनल्टी में बदला गया।
- **158** प्रावधानों में जुर्माना पूरी तरह हटा दिया गया।
- **113** प्रावधानों में जेल और जुर्माने की सजा हटाकर सिविल पेनल्टी लागू की गई।
- **57** प्रावधानों में जेल और जुर्माना दोनों खत्म किया गया।
- **63** प्रावधानों में पहली बार गलती पर चेतावनी/नोटिस का प्रावधान किया गया।
- **17** प्रावधानों में जेल की सजा घटाई गई जबकि 29 प्रावधानों में जेल की सजा हटा दी गई।
- **17** प्रावधानों में समझौते से मामला खत्म करने (कंपाउंडिंग) की सुविधा शुरू की गई।
- **9** अन्य प्रावधानों में कारावास की सजा को सिविल पेनल्टी में बदला या जेल की प्रकृति को तार्किक बनाया गया, अपराध के दायरे को सीमित किया गया।

विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020'



एमएसएमई की परिभाषा बदली गई। एमएसएमई के लोन को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक बिना गारंटी लोन उपलब्ध है। एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को 5 करोड़ रुपये तक के लोन सीमा को अनुमानित वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20% निर्धारित किया गया।



“

भारत ने पिछले दशक में शासन की संस्कृति में आए बदलाव का अनुभव किया है। जब निर्णय समय पर लिए जाते हैं, समन्वय प्रभावी होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार के संचालन की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसका प्रभाव सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



ईज ऑफ लिविंग

क्रांतिकारी बदलाव

ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सुगमता सबका अधिकार है। नए भारत के शीर्ष नेतृत्व की इस सोच के निहितार्थ 'केवल विशेष वर्ग' नहीं, बल्कि ग्रामीण, गरीब, आदिवासी, मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना है। केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में न केवल राष्ट्र के सपनों को बड़े स्तर पर देखा बल्कि गरीबी से निकल कर मध्यम वर्ग बनने में मदद करने और सुविधा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को परिपूर्णता (सैचुरेशन) तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम किया। इसलिए ईज ऑफ लिविंग अब शब्द नहीं, बन गया है सरकार का मंत्र...

- नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार सरल कराधान, नागरिकों पर कम बोझ और व्यापार करने की आसानी में सुधार की ओर निर्णायक कदम हैं। आमजन को अब कई तरह के कर की उलझन से मुक्ति मिली।
- 'ईज ऑफ लिविंग में सुधार लाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि की जिससे यात्रा सुगम हुई।
- ईज ऑफ लिविंग इंडैक्स 2025 में पुणे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, तिरुपति और चंडीगढ़ टॉप 5 शहरों में शामिल हैं।
- सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 का व्यापक पुनर्गठन कर नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू किया। कर विधान को सरल और सुव्यवस्थित करने से यह अधिक सुलभ, पारदर्शी होगा। अनुपालन आसान होने से आमजन का जीवन आसान होता है।
- पर्यटकों की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 और 1363 हेल्पलाइन शुरू की है। 10 अंतरराष्ट्रीय सहित 12 भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है।
- श्रमिक कल्याण और श्रमिकों का जीवन आसान करने के लिए 29 पुराने कानूनों को खत्म कर 4 श्रम कोड लागू किए।



1.90 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र घर बैठे जमा किए गए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुगम बनाया है।

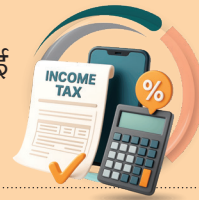


58.18

करोड़ जनधन खाते खोले गए जिससे आमजन की बैंकिंग, सरकारी सब्सिडी लाभ की सुगमता में वृद्धि हुई।

₹12
लाख

तक की वार्षिक आय पर नई कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं।



₹75,000

की मानक कटौती वेतनभोगी करदाताओं के लिए अतिरिक्त है।

3.3 करोड़
9.19 करोड़

2013-14 2024-25
ITR दाखिलकर्ता करदाता संख्या

₹314
लाख करोड़

से अधिक की ट्रांजैक्शन 2025-26 में यूपीआई से हुई। यह बीते 10 वर्षों में 12 हजार गुना वृद्धि है।



वैश्विक स्तर पर रियल टाइम भुगतान में भारतीय

UPI हिस्सेदारी **49%**

700 से अधिक बैंक जुड़े। आज करीब 54 करोड़ लोग UPI का उपयोग कर रहे हैं।



“

जीवन सुगमता हर नागरिक का अधिकार है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो कि देश के नागरिकों की *Ease of Living, Quality of Life* दिनों-दिन बेहतर होनी चाहिए, यही हमारी कसौटी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह भारत में रहने का सबसे अच्छा समय है। आज के भारत में व्यापार करना और लोगों का जीवन भी आसान बन रहा है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुविधाएं जिससे आसान हुआ जीवन



1.15

करोड़ लोगों का हर दिन जीवन आसान कर रही है मेट्रो रेल

1155

किलोमीटर का नेटवर्क देश के 26 शहरों में फैला है।



12 करोड़ शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन में

- 4 करोड़ से अधिक आवास पीएम आवास योजना में वितरित किए गए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी हर मौसम में निवास आसान हुआ।
- 10.56 करोड़ गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए जिससे धुएं के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाला न सिर्फ बुरा प्रभाव खत्म हुआ बल्कि समय की भी बचत हुई। लकड़ी लाने या उपले के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत हुई।
- 9.3 करोड़ यात्री ले चुके एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सुविधा का लाभ, 38 एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सुविधा है शुरू।
- 5.87 लाख सिटीजन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवा दे रहे हैं दिसंबर, 2025 तक देश में, यहां दी जाती हैं 800 से अधिक तरह की सेवाएं। घर के नजदीक डिजिटल सेवाओं की पहुंच से जीवन आसान हुआ।
- 102.86 करोड़ हुई दिसंबर, 2025 में इंटरनेट यूजर की संख्या, 2014 में थी महज 25 करोड़, 300% से अधिक की वृद्धि। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से भारत विश्व के तीन शीर्ष देशों में शामिल।
- 25 जीबी प्रति माह औसतन डेटा इस्तेमाल करते हैं प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर, उच्च आय वाले देशों में 17.9 जीबी है। प्रति जीबी डेटा लागत 2014 में 308 रुपये से घटकर अब 7.87 रुपये हुई। डेटा की किफायती पहुंच से डिजिटल सेवाओं से जीवन आसान हुआ।

1.64

करोड़ से अधिक यात्री ले चुके हैं उड़ान योजना का लाभ।

665

रूट से 95 एयरपोर्ट-हेलिपोर्ट और वाटर एयरोड्रॉम कनेक्टेड हैं।

74

2014

165

2026

एयरपोर्ट की संख्या





अष्टलक्ष्मी

नए भारत की शांति-समृद्धि की ताकत 'अष्टलक्ष्मी'

अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के आठ राज्य, आत्मविश्वास से भरे हैं। नई दिशा पर चल पड़े हैं और राष्ट्र की विकास यात्रा का नेतृत्व करने को तत्पर हैं। कभी हिंसा और नाकाबंदी की पहचान और 5 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह क्षेत्र अब विकास पथ पर चलते हुए सर्वांगीण विकास का साक्षी बन रहा है। बीते 12 वर्षों में विकास की इस नई धारा ने सिद्ध किया है कि अब पूर्वोत्तर आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का प्रवेश द्वार है जो न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर...

पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान, दिल्ली से बढ़ा जुड़ाव

- पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत से सीधा जुड़ाव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री, उनके मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करते रहे हैं।
- सरकार ने तय किया है कि हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री किसी न किसी पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं तो जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2025 के बीच केंद्रीय मंत्रियों ने 880 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है।



10% की बजटीय सहायता

इस व्यवस्था के तहत 55 मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर के विकास पर खर्च करते हैं। इन प्रयासों से पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है।



बजट में खर्च ऐतिहासिक विस्तार

2014-15
2025-26

₹ 24,819 करोड़

₹ 1,00,271 करोड़



बीते 12 वर्षों में पूर्वोत्तर को भरपूर राशि मिली

कुल बजट आवंटन

6.97

लाख करोड़ रुपये

वास्तविक खर्च

7.12

लाख करोड़ रुपये



पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं विकास कार्य

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लगभग

3,735

परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है

49,907

करोड़ रुपये जिनकी कुल लागत है।



विकास परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश, बढ़ी कनेक्टिविटी...

- बोगीबील ब्रिज : 2018 में उद्घाटन (जिसकी घोषणा 16 साल पहले हुई थी)।
- पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं।
ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 2014 में 9 थी जो 2026 में 17 हो गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 में 10,905 किमी थी,
1 अप्रैल 2025 तक 16,207 किमी हो गई। 87 हजार करोड़ रुपये से
अधिक लागत की 3,634 किमी लंबी 177 सड़क परियोजनाएं विभिन्न
चरणों में क्रियान्वयन में हैं।
- NESIDS योजना में 72 परियोजनाएं पूरी, 997.55 किमी सड़क बनीं।
अभी 911 के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

89,503

किमी लंबी 17,666 सड़कों और
2,396 पुलों को मंजूरी दी गई।



81,448

किमी लंबी 16,547 सड़कें और 2,126
पुल इनमें से बनकर तैयार हो चुके हैं।

53,353.49

करोड़ रुपये
खर्च हुए हैं



“

नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक
अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि
ये भारत की 'अष्ट लक्ष्मी' हैं।
इसलिए, हम 'एक्ट ईस्ट' की
पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे
हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए 'एक्ट
फास्ट' का संकल्प भी लिया है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आजादी के बाद पहली बार

2022

में मणिपुर में पहली
मालगाड़ी पहुंची।

2023

में मेघालय में पहली
मालगाड़ी पहुंची।

2025

में मिजोरम में
पहली ट्रेन पहुंची।



वयुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



राष्ट्र प्रथम सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित भारत

राष्ट्ररक्षासमं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्। राष्ट्ररक्षासमं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव चा।

अर्थात् राष्ट्र की रक्षा से बड़ा न कोई पुण्य है, न कोई व्रत है और न ही कोई यज्ञ है।

सात पड़ोसी देशों से जुड़ी 15 हजार किमी से लंबी सीमा और साढ़े सात हजार किमी से ज्यादा लंबी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए 'राष्ट्र प्रथम' की नीति के साथ भारत आज अपनी प्रभावी विदेश नीति को संचालित कर रहा है तो रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर केंद्र सरकार संकल्पित है तो प्रतिबद्ध भी। दुनिया ने ये प्रतिबद्धता उरी में सैनिक कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद देखी है तो पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर कायराना हमले के बाद भी। बीते वर्ष ही 6-7 मई 2025 की मध्य रात्रि को 'ऑपरेशन सिंदूर' से दुनिया को संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी राष्ट्र के लिए सैन्य शक्ति का सशक्त होना जरूरी है, लेकिन शक्ति बनने के लिए युद्ध या सेना ही सर्वोपरि नहीं है। बीते 12 वर्ष में दुनिया में योग, विश्व में अपनी अलग छवि का निर्माण किया है तो हर संकट में अपनों और दुनिया के अन्य लोगों के लिए मददगार के रूप में उभरना, कोविड जैसी वैश्विक आपदा को अवसर बनाकर दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करना या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई क्रांति का सूत्रपात करना, भारत एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भी नई पहचान बना रहा है।

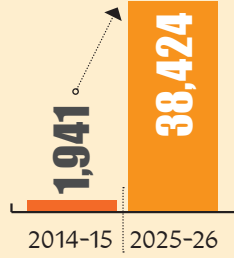
विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान

भारत आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और समावेशी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विस्तार, महिला सशक्तीकरण और युवा नेतृत्व ने देश को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाई है। 'सशक्त भारत' केवल एक सपना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सामूहिक प्रयास और संकल्प का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जो विकास और विश्वास की लिख रहा है नई कहानी...

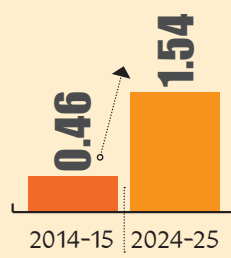
सशक्त भारत के महत्वपूर्ण तथ्य...

- भारत वर्ष 2018 से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना हुआ है। वर्ष 2014 में वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 5.2% थी जो 2024 में बढ़कर 7.9% हो गई है।
- **फार्मसी ऑफ वर्ल्ड** : आज भारत उत्पादन की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा औषधि उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का वार्षिक कारोबार 4.72 लाख करोड़ रुपये दर्ज हुआ।
- करीब 65% रक्षा उपकरण आज देश में ही निर्मित हो रहे हैं, जबकि पहले लगभग 65-70% आयात किए जाते थे।
- भारत, आज दुनिया की कुल जेनेरिक दवाओं का पांचवां हिस्सा और यूनिसेफ के लिए आधे से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है।
- भारत 'शक्ति' पहल, मेडिकल टूरिज्म और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के निर्यात के माध्यम से 300 अरब डॉलर की बायोफार्मा महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नेटवर्क का विस्तार करते हुए 38 देशों के साथ नौ समझौते किए हैं।
- भारत ने पहली बार 'अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन' पर आईएसओ की अंतरराष्ट्रीय उपसमिति की बैठकों की मेजबानी की।

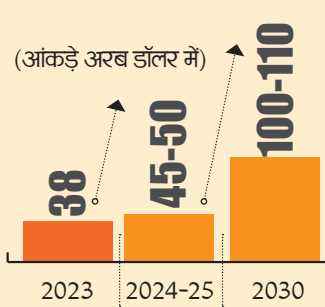
रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी (आंकड़े करोड़ रुपये में)



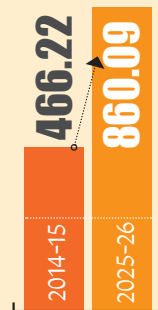
रक्षा उत्पादन (आंकड़े लाख करोड़ रुपये में)



भारतीय सेमीकंडक्टर का बढ़ता बाजार (आंकड़े अरब डॉलर में)



भारत का कुल निर्यात (आंकड़े अरब डॉलर में)



भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बढ़ा
मार्च, 2014 **91,287** किमी
फरवरी, 2026 **1,46,572** किमी

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत

पंजीकृत स्टार्टअप

1 से अधिक
2014 से अब

विदेशी उपग्रह

- **ISRO** द्वारा प्रक्षेपित 434 विदेशी उपग्रहों में से 399 उपग्रह 2014 के बाद प्रक्षेपित किए गए हैं। इन प्रक्षेपणों ने भारत को लगभग 323 मिलियन यूरो और 233 मिलियन डॉलर का राजस्व दिलाया है।
- लगभग 8.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था।



दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक का अनुमान... भारत की अर्थव्यवस्था 2026-27 में लगभग 6.6% की दर से बढ़ेगी। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।

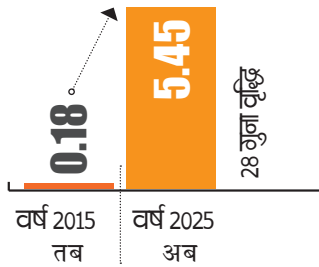
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार भारत की विकास दर 6.5% का अनुमान है जबकि विकसित देशों के लिए 1.8%, विकासशील देश के लिए 3.9%, पूरी दुनिया के लिए 3.1% रखी गई है।



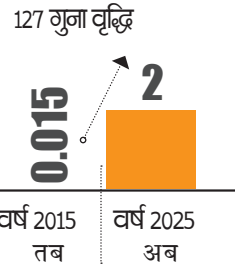
भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का पावरहाउस

(आंकड़े लाख करोड़ रुपये में)

मोबाइल विनिर्माण उत्पादन मूल्य



मोबाइल फोन निर्यात



सशक्त भारत की पहचान

एआई में सशक्त भारत

एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और उसके पीछे एआई की मदद से त्वरित सांकेतिक भाषा में दिव्यांग लोगों के लिए उसे ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है।

साहसिक फैसले वाला सशक्त भारत

कश्मीर में दशकों से लंबित एक संविधान-एक विधान को लागू करने में आड़े आ रही अनुच्छेद 370 खत्म किया। अब वह सभी कानून कश्मीर में लागू हैं जो देश के बाकी राज्यों में हैं।

नारी नेतृत्व वाला सशक्त भारत

लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की तीन दशक से चली आ रही बाधा को तोड़कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिसूचित किया। 1996 के बाद प्रयास हुए लेकिन नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पास हुआ।

अंतरिक्ष में सशक्त भारत

भारत अब चांद तक पहुंचा है, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर विश्व का कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंचा था।

उपनिवेशवाद को खत्म करता सशक्त भारत

'पंचामृत' के आह्वान से देश में उपनिवेशवाद की यादें खत्म की जा रही हैं। अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा लगाना, नौसेना के ध्वज को बदलना, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी तोपों से सलामी।

आपदा जोखिम प्रबंधन अभियान

- ऑपरेशन मैत्री (नेपाल, 2015)
- ऑपरेशन देवी शक्ति (अफगानिस्तान, 2021)

सागर मिशन के अंतर्गत नौसेना द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाना

- ऑपरेशन समुद्र सेतु (2020)
- ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन, 2022)
- ऑपरेशन दोस्त (तुर्किये और सीरिया, 2023)
- ऑपरेशन कावेरी (सूडान, अप्रैल 2023)
- ऑपरेशन ब्रह्मा (म्यांमार, 2025)
- ऑपरेशन सागर बंधु (2025)



“

रणनीतिक स्वायत्तता और स्वदेशी क्षमताएं खतरों से निर्णायक रूप से निपटने की कुंजी हैं, जो आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय शक्ति, गरिमा और 2047 तक एक विकसित भारत बनने की यात्रा का आधार बनाती हैं।

-नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री



ऑपरेशन सिंदूर

नौ आतंकी शिविर नष्ट

भारत ने लश्कर-ए-तैबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में स्थित नौ प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

सीमा पार सटीक हमले

भारत ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों, जिनमें पंजाब प्रांत और बहावलपुर भी शामिल है, पर हमले करके युद्ध के नियमों को फिर से परिभाषित किया। ये इलाके कभी अमेरिकी ड्रोन के लिए भी वर्जित माने जाते थे।

एक नई रणनीतिक सीमा रेखा

ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सीमा रेखा खींच दी-यदि आतंकवाद किसी देश की नीति है, तो इसका प्रत्यक्ष और बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा।

भारत की वायु रक्षा श्रेष्ठता का प्रदर्शन

स्वदेशी आकाशतंत्र प्रणाली सहित भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। इससे उन्नत रक्षा प्रणालियों के निर्यात में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।

पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले

9-10 मई को, भारत परमाणु हथियार संपन्न देश के 11 हवाई अड्डों पर एक ही अभियान में हमला करने वाला पहला देश बन गया, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना की 20% संपत्ति नष्ट हो गई।

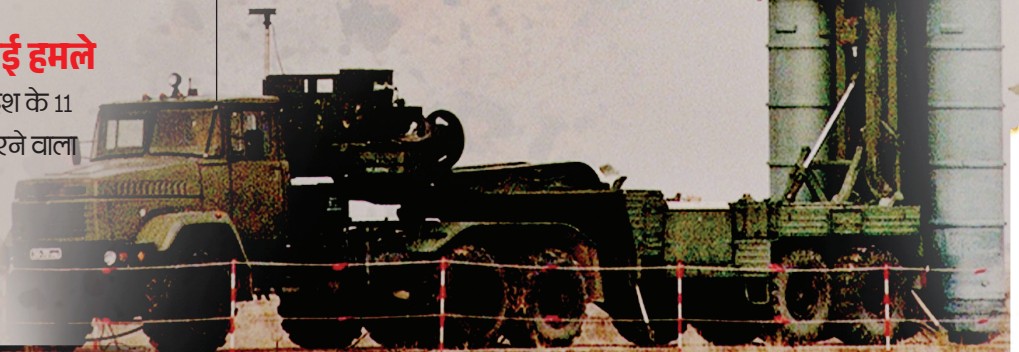
भारत ने वैश्विक संदेश दिया

भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसे अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसने इस विचार को पुष्ट किया कि आतंकवादी और उनके सरगना कहीं भी छिप नहीं सकते और यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है, तो भारत निर्णायक जवाबी हमले के लिए तैयार है।



व्यापक वैश्विक समर्थन

पिछले संघर्षों के विपरीत, इस बार कई वैश्विक नेताओं ने संयम बरतने की अपील करने के बजाय भारत का समर्थन किया। इस बदलाव ने भारत की बेहतर वैश्विक स्थिति और कथात्मक नियंत्रण को दर्शाया।





विदेश नीति

विश्व पटल पर चमकता भारत

पिछले एक दशक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने न केवल अपनी पारंपरिक सीमाओं का विस्तार किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की भूमिका को भी नई परिभाषा दी है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिवेश, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलित, सक्रिय और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी कूटनीतिक पहचान को सशक्त बनाया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने से लेकर वैश्विक शक्तियों के साथ साझेदारी को गहराने तक, भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका...

मुक्त व्यापार समझौता

- भारत ने वैश्विक व्यापार की दिशा को नए सिरे से परिभाषित किया है। नए दौर के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का मार्ग प्रशस्त किया है।
- पिछले कुछ वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों के अपने दायरे को भारत ने विस्तार दिया है। अब तक 38 देशों के साथ कुल नौ एफटीए हो चुके हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में भारत-मॉरीशस समझौते से हुई थी।

जी20 की अध्यक्षता 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का समर्थन

- 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की जी20 अध्यक्षता ने वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय का सूत्रपात किया।
- 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य देशों, नौ आमंत्रित देशों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।
- भारत ने 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी की, जिसमें एक लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

विकासशील देशों की मुखर आवाज

- ग्लासगो में कॉप-26 और शर्म-अल-शेख में कॉप 27 की बैठक में विकासशील देशों की मुखर आवाज बनकर उभरा भारत।

वैक्सीन मैत्री



- कोविड-19 संकट के दौरान, भारत ने अपनी मानव-केंद्रित कूटनीति के प्रमाण के रूप में वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की।
- जनवरी 2021 से, भारत ने 99 देशों और दो संयुक्त राष्ट्र निकायों को 30.12 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराकें उपलब्ध कराई हैं।
- त्वरित और व्यापक सहायता ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय भागीदार और वैश्विक दक्षिण से एक सहानुभूतिपूर्ण आवाज के रूप में भारत की छवि को मजबूत किया।

50 से अधिक देशों को उपहार स्वरूप दी गई वैक्सीन की 1.51 करोड़ खुराकें।



अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन



- 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा होलांद द्वारा शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत का प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है।

120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ, ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1,000 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है।

- गुरुग्राम में मुख्यालय वाला यह भारत में स्थित पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी निकाय है।

संकट के समय में भारत अग्रणी



- भारत ने 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है।
- जुलाई 2021 में, विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय एजेंसियों और विदेशी सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ की स्थापना की।

पड़ोस को प्राथमिकता

- भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति ने क्षेत्रीय संबंधों के प्रति एक साहसिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को आकार दिया है।
- यह नीति भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ मजबूत भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता देती है।

नए दूतावास और वाणिज्य दूतावास



40 से ज्यादा नए दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारत ने विश्वभर में 2014 से 2025 के बीच खोले।

इनकी कुल संख्या **220** हो गई है। इस विस्तार ने भारत की वैश्विक उपस्थिति और पहुंच को और मजबूत किया है।

विदेशों में रोजगार अवसर

- पिछले एक दशक में भारत ने सऊदी अरब, फ्रांस, यूएई, जापान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, जर्मनी सहित डेढ़ दर्जन से ज्यादा देशों के साथ मोबिलिटी और प्रवास साझेदारी की है। इससे भारतीय नागरिकों के लिए विदेश में रोजगार के अवसर खुले हैं।





राहत और निकासी अभियान

- बीते 10-12 वर्षों में भारत की विदेश नीति न केवल कूटनीति और संवाद पर आधारित रही है, बल्कि विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा खतरे में होने पर निर्णायक कार्रवाई करने पर भी केंद्रित रही है। राहत और निकासी प्रयास 'राष्ट्र सर्वोपरि' नीति के प्रमुख उदाहरण बन गए हैं। चाहे महामारी हो, संघर्ष संकट हो, राजनीतिक उथल-पुथल हो या प्राकृतिक आपदा, भारत ने अपने लोगों को सुरक्षित और शीघ्रता से घर वापस लाया है।

प्रमुख निकासी अभियान



- वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन इंद्रावती सहित कई अन्य अभियान भारत सरकार की पहल पर चलाए गए।

सर्वोच्च नागरिक सम्मान से बढ़ा भारत का मान



- अप्रैल 2026 तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 से अधिक विभिन्न देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जो उन्हें इतिहास में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान पाने वाला भारतीय नेता बनाता है।

आतंक पर सख्त नीति



आतंकी हमलों का कड़ा जवाब

- भारत पर किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा, चाहे हमलावर कहीं से भी काम कर रहे हों।

परमाणु ब्लैकमेल के प्रति कोई सहनशीलता नहीं

- भारत परमाणु धमकियों से भयभीत नहीं होगा। आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करना जारी रखेगा।

आतंकी तत्वों में कोई भेद नहीं

- आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं और प्रायोजकों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

वार्ता में आतंकवाद को प्राथमिकता

- पाकिस्तान के साथ यदि कोई बातचीत होती भी है, तो वह केवल आतंकवाद या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर ही केंद्रित होगी।

संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं

- 'आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते,' आतंकी खतरों के बीच सामान्य संबंधों के दरवाजे को दृढ़ता से बंद किया गया।



आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई मुखर है और वह एक हमले को भी कई हमलों की तरह मानता है। भारत यह भी मानता है कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। यह मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। इसलिए आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर केंद्र सरकार संकल्पित है। दुनिया ने यह प्रतिबद्धता उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में देखी भी है। सटीक, कड़ा और निर्णायक प्रहार करते हुए दुनिया को संदेश दिया गया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को कतई नहीं किया जाएगा बर्दाश्त...

ऑपरेशन सिंदूर

- अप्रैल 2025 में, पहलगाम में नागरिकों पर कूर आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।
- पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों पर सटीक जवाबी हमले किए गए।
- भारतीय सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार किए बिना खतरों को बेअसर करने के लिए ड्रोन हमले, गोला-बारूद और बहुस्तरीय हवाई रक्षा का उपयोग किया।
- भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर सटीक हमला किया, नूर खान एयर

बेस और रहीमयार खान एयर बेस जैसे लक्ष्यों पर हवाई अभियान।

- नौसेना ने मिग-29के लड़ाकू विमानों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी हेलीकॉप्टर से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप (सीबीजी) को तैनात किया।
- सामरिक सफलता के साथ-साथ रणनीतिक संदेश भी था। थल, वायु और समुद्र में समन्वित सैन्य कार्रवाई करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन।
- जकोबाबाद में शाहबाज एयरबेस पर हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें विनाश को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
- हमले में सरगोधा और भोलारी जैसे प्रमुख

गोला-बारूद डिपो तथा एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां एफ-16 व जेएफ-17 लड़ाकू विमान तैनात थे। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान की वायु सेना का लगभग 20% बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया।

- भोलारी एयरबेस पर बमबारी में स्ववाइन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 वायुसैनिकों सहित 50 से अधिक मारे गए। कई पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भी नष्ट कर दिए गए थे।
- ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लाल रेखा खींच दी है-अगर आतंकवाद किसी देश की नीति है, तो इसका स्पष्ट और सशक्त जवाब दिया जाएगा।

महज **तीन घंटे** के अंदर भारत ने नूर खान समेत **11 सैन्य ठिकानों** रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कर्टू, भोलारी और जैकोबाबाद को निशाना बनाया।



भारत और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ हुए एकजुट

- आतंकवाद से जुड़े फंडिंग को रोकने के लिए एफएटीएफ अनुपालन पर जोर।
- मिलिपोल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में भारत के आतंकवाद निरोधी नेतृत्व का प्रदर्शन।
- अप्रैल 2024 में भारत-फ्रांस आतंकवाद विरोधी संवाद का आयोजन।



भारत और अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा

- आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क को नष्ट करने हेतु भारत और अमेरिका की एकजुटता।
- अल कायदा, आइएसआइएस, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोएबा जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई।
- 26/11 और आबे गेट हमलावरों को कड़ा जवाब
- अमेरिका ने 26/11 के साजिशकर्ता तहक्कुर राणा को भारत के सुपुर्द किया।
- पाकिस्तान से 26/11 और पठानकोट हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील।

दुनिया भर में आतंकवाद फंडिंग के खिलाफ मुहिम

- 2022 में भारत ने 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन की मेजबानी की।
- भारत द्वारा वैश्विक क्रिप्टो विनियमन को बढ़ावा देने पर जोर।



- भारत ने 28-29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी में 18 सैनिकों पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब दिया।
- इन हमलों ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को भारी नुकसान पहुंचाया।
- 14 फरवरी 2019 को, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने तेज कार्रवाई की। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमलों में वरिष्ठ कमांडरों सहित बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया गया।
- पूर्व-प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब आतंकवाद के माध्यम से छद्म युद्ध को सहन नहीं करेगा।



सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक

मसूद अजहर वैश्विक आतंकी घोषित

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया।
- 2019 में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत सिद्ध हुई।

एक नए एवं सुरक्षित भारत की ओर...

- 2010 से 2024 तक आतंकवाद से होने वाले मौतों में 85 प्रतिशत की कमी आई।
- जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं 2019 से 70 प्रतिशत कम हुईं।





आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

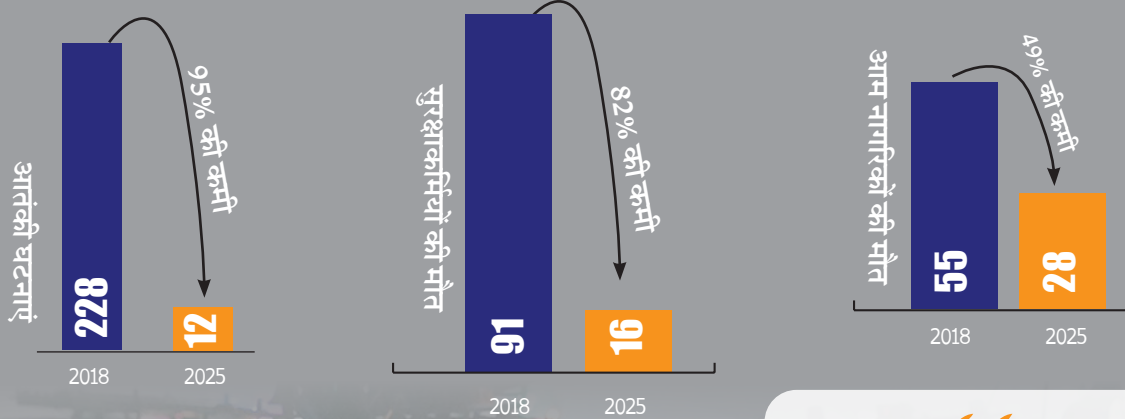
- 2 अगस्त 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर नए अपराधों को शामिल करने के साथ ही एनआईए को विदेश में भी जांच का अधिकार मिला है।
- **UAPA** में भी संशोधन करके आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने और व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला है।
- वर्तमान केंद्र सरकार ने कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया।

मजबूत नीतियों से सुरक्षित भारत

- बीते 10 वर्षों में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी
- यूएपीए मामलों में एनआईए की 95 प्रतिशत सजा दर, मजबूत आतंकवाद विरोधी नीति

15 से अधिक संगठनों पर आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंध

आतंकी घटना



“कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इन देशों को अलग-थलग कर देना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का अगर-मगर नहीं होना चाहिए।”

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री





नक्सल

नक्सल मुक्त भारत : नए भारत की नई कहानी

भारत नक्सलवाद, माओवादी आतंक से मुक्त हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 12 साल में भारत की यह सबसे बड़ी सफलताओं में सबसे महत्वपूर्ण है। बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने देश का संविधान विजयी हुआ है। कल तक जो रेड कॉरिडोर थे, वह आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। समयबद्ध तरीके से दशकों पुरानी समस्या की समाप्ति यानी नक्सल मुक्त भारत के संकल्प ने 31 मार्च 2026 को संघर्ष से सिद्धि का रच दिया ऐतिहासिक अध्याय...

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए काम

2014 से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में

17,589 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है

12,000 किमी सड़कें पहले ही बन चुकी हैं।

6,025 डाकघर खोले गए हैं।



8,000 4G टावर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

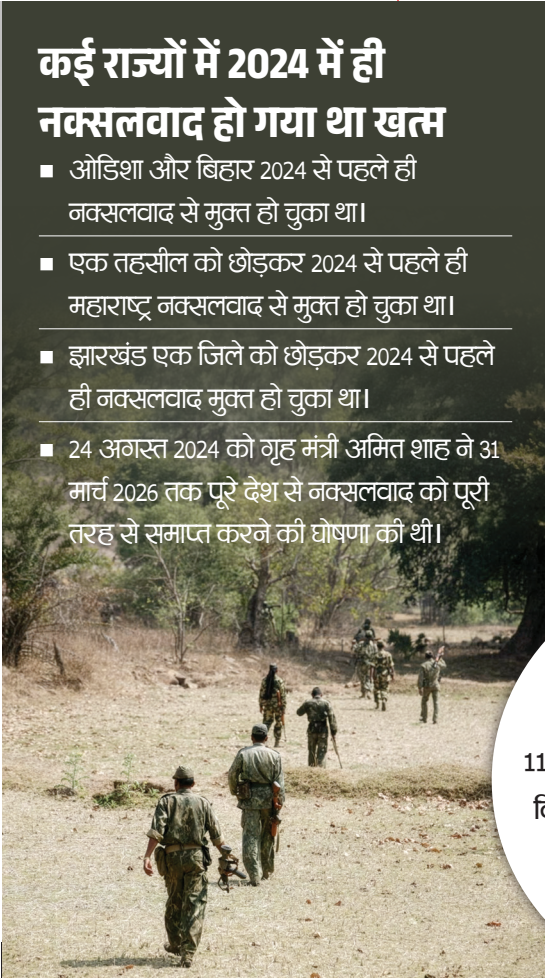
₹6,000 करोड़ की लागत से लगभग 5,000 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं।

पिछले 12 वर्षों में **1,804** बैंक शाखाएं खोली गई हैं, **1,321** एटीएम स्थापित किए गए हैं।



कई राज्यों में 2024 में ही नक्सलवाद हो गया था खत्म

- ओडिशा और बिहार 2024 से पहले ही नक्सलवाद से मुक्त हो चुका था।
- एक तहसील को छोड़कर 2024 से पहले ही महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त हो चुका था।
- झारखंड एक जिले को छोड़कर 2024 से पहले ही नक्सलवाद मुक्त हो चुका था।
- 24 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की थी।



वामपंथी उग्रवादियों और उनके समर्थकों ने भोले भाले आदिवासियों के सामने एक गलत प्रकार का नरेटिव रखा था कि वे उनके अधिकारों और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं।

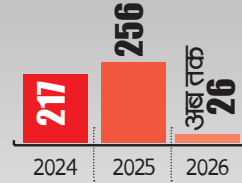
-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

नक्सलवाद खत्म करने के लिए उठाए गए कदम

11 वर्षों में **596** सबसे अधिक प्रभावित किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए गए।

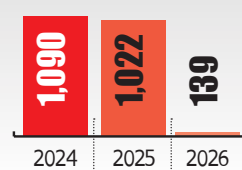


माओवादी मारे गए



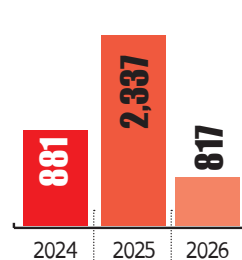
(नोट : 30 मार्च 2026 तक के आंकड़े।)

गिरफ्तार किया गया



(नोट : 30 अप्रैल 2026 तक)

आत्मसमर्पण





सरकार की नीतियों का असर

- नक्सलियों से जख्त किए गए हथियारों में से **92%** पुलिस से लूटे गए थे।
- नक्सलियों के महासचिव बसवरजू को मार गिराया गया।
- **27** लोगों की हत्या करने वाले हिडमा को मार गिराया गया।
- **11** वर्षों से सक्रिय गजुरेल्ला रवि को मार गिराया गया।
- **46** वर्षों से सक्रिय कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराया गया।
- **44** वर्षों से सक्रिय गणेश उड्डेके को मार गिराया गया।
- **46** वर्षों से सक्रिय वेणुगोपाल और पल्लूरी प्रसाद राव चंदना ने आत्मसमर्पण किया।
- **36** वर्षों से सक्रिय वासुदेव व रामदेव मांझी देबू ने आत्मसमर्पण किया।
- **44** वर्षों से सक्रिय रहे तिप्पी तिरुपति ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है।
- बचे सभी शीर्ष सशस्त्र माओवादी नेताओं को मार गिराया गया।

नक्सलबाड़ी

नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन 12 राज्यों में फैल गया

जिसमें देश का

17% से **10%** अधिक भूभाग जनसंख्या शामिल थी।

नक्सली उन्मूलन के लिए ऑपरेशन



ऑपरेशन ऑक्टोपस: बिहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में वर्ष 2022 में चला।

ऑपरेशन डबल बुल: झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में चला फरवरी 2022 में चला। तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए।

ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म: झारखंड के सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में सितंबर 2022 में चला।

ऑपरेशन भीमबर्ग: मुंगेर जिले में जून व जुलाई 2022 में चला।

ऑपरेशन चक्रबांधा: बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में 2022 में चला।

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किमी लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी पर वर्ष 2025 में चला।

विशेष कोर्ट और जांच एजेंसियों का गठन

- एनआईए को काफी मजबूत किया गया है और एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों (एसआईए) को भी स्थापित किया गया।
- छत्तीसगढ़ में 4 एलडब्ल्यूई स्पेशल कोर्ट शुरू किए गए और दूसरे राज्यों में भी एक्सक्लूसिव कोर्ट की स्थापना की गई।

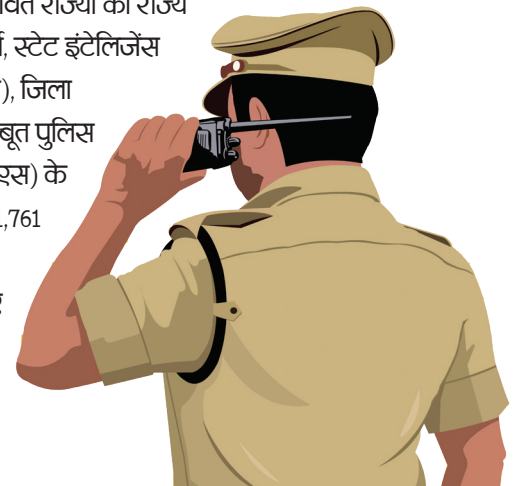
आर्थिक रूप से किया गया कमजोर

नक्सलियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सक्रिय करके एक आक्रामक रणनीति अपनाई गई। जिसके परिणामस्वरूप उनके वित्तीय संसाधनों की कमी आई।



पुलिस बल का आधुनिकीकरण

- राज्यों की पुलिस फोर्स को लैस करने और आधुनिक बनाने की कोशिशों को 'पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण' की योजना के तहत सहायता दी गई।
- योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियार, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उपकरण, कम्प्युनिकेशन, ट्रेनिंग, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, मोबिलिटी और पुलिस आवास और अन्य पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए केंद्र सरकार ने मदद दी।
- स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआईएस) के तहत, एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को राज्य की स्पेशल फोर्स, स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच (एसआईबी), जिला पुलिस और मजबूत पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण के लिए 1,761 करोड़ रुपये के काम मंजूर किए गए थे।





आवरण कथा
विकास यात्रा के
12 वर्ष

विकास भी, विरासत भी

सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित भारत

राष्ट्रीय एकता हो या फिर नागरिक कर्तव्य बोध, सांस्कृतिक विरासत कड़ी का काम करती है। यही वो मजबूत कड़ी है जो देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत से जोड़ती है। इसी सोच से सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते भारत ने अपने अद्भुत गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम जोड़कर विकास और विरासत को आत्मसात करते हुए बीते 12 वर्षों में लिख दी है सुनहरे भविष्य की पटकथा। साथ ही, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर वसुधैव कुटुम्बकम् के मंत्र को अपनाते हुए भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी विश्व का मार्गदर्शक बनकर उभरा है। दुनिया की कई संस्थाओं की मुखर आवाज बनकर भारत ने मिशन लाइफ और प्रकृति के साथ समन्वय की नई राह दुनिया को दिखाई है। पर्यावरण प्रतिबद्धता में नेतृत्व का युग प्रशस्त करते हुए भारत ने कर दिया है नए अध्याय का सूत्रपात...

अतीत की पहचान, भविष्य की दिशा

भारत की विरासत उसकी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतिबिंब है। विविधताओं से भरे इस देश में ऐतिहासिक स्मारक और जीवन शैली पहचान को समृद्ध बनाते हैं। आज के दौर में विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि विकास और आत्मगौरव का आधार भी है। सरकार द्वारा संरक्षण, संवर्धन और डिजिटल दस्तावेजीकरण जैसे प्रयासों के माध्यम से इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी से जोड़ा जा रहा है। यह पहल न केवल हमारी जड़ों को मजबूत करती है, बल्कि भारत को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर बनाती है और सशक्त...

नया संसद भवन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
- 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने ही नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी।



गुलामी की मानसिकता से मुक्ति



- राष्ट्रीय नायक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट के पास स्थापित की गई है, जिसने वहां पहले स्थापित किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा का स्थान लिया है।
- गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ इतिहास का विषय बन गया और सितंबर 2022 इसे कर्तव्य पथ में बदल दिया गया।
- रेस कोर्स रोड हुआ 7 लोक कल्याण मार्ग, वर्ष 2016 में।
- डलहौजी रोड हुआ अब दारा शिकोह रोड, वर्ष 2017 में।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक स्वतंत्रता के बाद से वीर सैनिकों के बलिदान का साक्षी है।



- भारतीय नौसेना के लिए राष्ट्रपति ध्वज और रंग तथा भारतीय नौसेना प्रतीक चिन्ह के नए डिजाइन का अनावरण 4 दिसंबर 2022 को नौसेना दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में किया गया।



- गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के तहत नौसेना को नया ध्वज मिला जिसे शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ा गया।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया।

1,500 कानून औपनिवेशिक शासन काल के खतम।



प्रधानमंत्री संग्रहालय

- 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को मान्यता देता है और दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग और स्तर के नेताओं को राष्ट्र में योगदान करने का अवसर प्रदान किया है।



खोई हुई विरासत को वापस लाया गया

- 2014 से, 653 से ज्यादा चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं को देश में वापस लाया गया।
- 2013 से पहले, विदेश से भारत केवल 13 चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लाई गई थीं।



2016 से, अमेरिकी सरकार ने तस्करी या चोरी की गई कई प्राचीन वस्तुओं की वापसी की सुविधा प्रदान की है।

2016 से अमेरिका से भारत को वापस की गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की कुल संख्या 578 है। यह किसी भी देश द्वारा भारत को वापस की गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की अधिकतम संख्या है।

यूनेस्को : विरासत के मील के पत्थर

पिछले एक दशक में, भारत ने विश्व विरासत सूची में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। भारत में अब विश्व विरासत सूची में 44 स्थल और यूनेस्को की संभावित सूची में 69 स्थल हैं। इन स्थलों को न केवल इतिहास के प्रतीक के रूप में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने की जगह के रूप में भी संरक्षित किया जाता है।



डिजिटल अभिलेखीय रिकॉर्ड

- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान दस्तावेजों को संरक्षित करने और शोधकर्ताओं तथा आम जनता के लिए अभिलेखीय संसाधनों तक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से अभिलेखीय रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम आरंभ किया है।

अभिलेख पटल पोर्टल पर वर्तमान उपलब्ध सामग्री



18.98

करोड़
डिजिटाइज्ड
पेज

40.09

लाख
डिजिटाइज्ड
फाइल

74.03

लाख संदर्भ
मीडिया रिकॉर्ड

सकारात्मक विरासत का संरक्षण

- जब सफल राष्ट्र आगे बढ़ते हैं, तो अपनी सकारात्मक विरासत को त्यागते नहीं हैं, वो उसे संरक्षित करते हैं। आज 'विकास और विरासत' के इसी विजन पर भारत आगे बढ़ रहा है।
- नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भारत की महान विरासत का हिस्सा बनाया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देश की जनता के लिए 'युगे युगीन भारत', संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है। देश का हर नागरिक यहां जा सकेगा, देश की ऐतिहासिक यात्रा के दर्शन कर सकेगा।

पंच प्रण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सभी देशवासियों से 'पंच प्रण' - विकसित भारत के लक्ष्य को अपनाने, गुलामी की मानसिकता को दूर करने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने, एकता और अखण्डता के लिए पूरा जीवन समर्पित करने और हर नागरिक के मन में कर्तव्य की भावना जगाने का आह्वान किया।

स्मारकों का नया दौर : विरासत से नई प्रेरणा

- प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जलियावाला बाग स्मारक, बिप्लॉबी भारत गैलरी के निर्माण के साथ-साथ देश भर में 11 जनजातीय संग्रहालयों को मंजूरी।

वैश्विक पटल पर सांस्कृतिक पहचान

जब किसी देश की आर्थिक शक्ति के साथ सांस्कृतिक विरासत को स्वीकारा जाता है, तब सही अर्थों में वैश्विक पटल पर उस देश को सम्मान और पहचान मिलती है। यही वजह है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश के लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर हो रहा है गर्व...

राम मंदिर

- अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को भव्य श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा का समापन था।
- भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है।
- मंदिर की लंबाई (पूर्व-पश्चिम) 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है।
- मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का गूढ़ चित्रण है।
- भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप (श्री राम लला की मूर्ति) रखा गया है।
- श्रीराम मंदिर पर 25 नवंबर 2025 को भगवा ध्वज लहराने के साथ परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया।

भूमि पूजन और शिलान्यास

- पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया था।
- 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान की थी।
- 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि सर्वसम्मत और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए दे दी।



यह भव्य राम मंदिर भारत के उत्कर्ष और उदय का साक्षी होगा। यह भव्य राम मंदिर भारत की समृद्धि और विकसित भारत का साक्षी होगा।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठापन समारोह में 22 जनवरी 2024 को)





श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

5.5 एकड़ में फैली 355 करोड़ रुपये की परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर, 2021 को हुआ।

- यह गलियारा काशी विश्वनाथ मंदिर को चार लेन मार्ग द्वारा सीधे गंगा नदी से जोड़ता है। मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुगमता प्रदान करता है।

3,880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल को काशी में शुभारंभ किया।

- वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में विकास के तहत कुल 48,459 करोड़ रुपये की लागत से 580 परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ।



“

काशी आज केवल पुरातनता ही नहीं, प्रगति का भी प्रतीक है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



महाकाल लोक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया।
- 850 करोड़ रुपये है पूरी परियोजना की लागत।
- महाकाल पथ पर 108 स्तंभ हैं जिन पर भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाया गया है।
- महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां स्थापित हैं।
- पथ के किनारे बनी भित्तिचित्रों की दीवार पर शिव पुराण से सृष्टि की कथाएं, गणेश जी का जन्म, सती और दक्ष की कथा आदि अंकित हैं।
- परिसर की निगरानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कैमरों की सहायता से कमांड और नियंत्रण केंद्र द्वारा की जाती है।



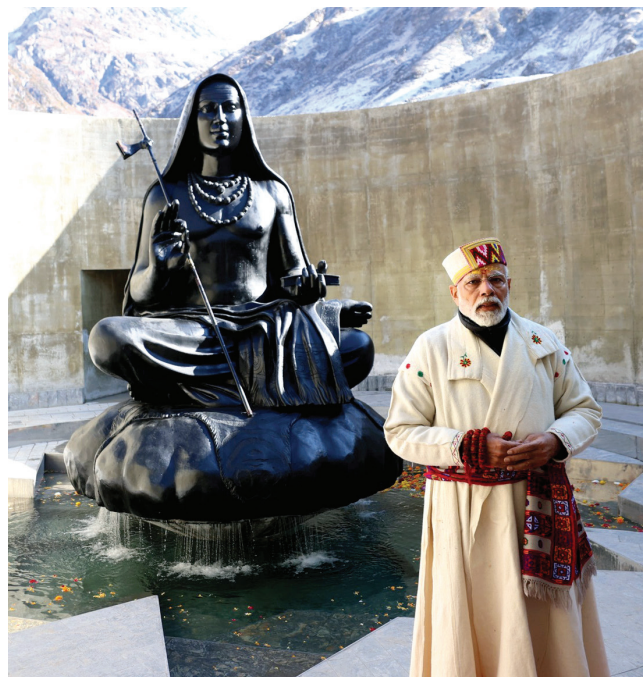
मां कामाख्या मंदिर, असम

मां कामाख्या मंदिर के विकास में बुनियादी ढांचे और तीर्थयात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे अधिक बेहतर सुविधाएं, आरामदायक और सुलभ आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित हुआ।



केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड

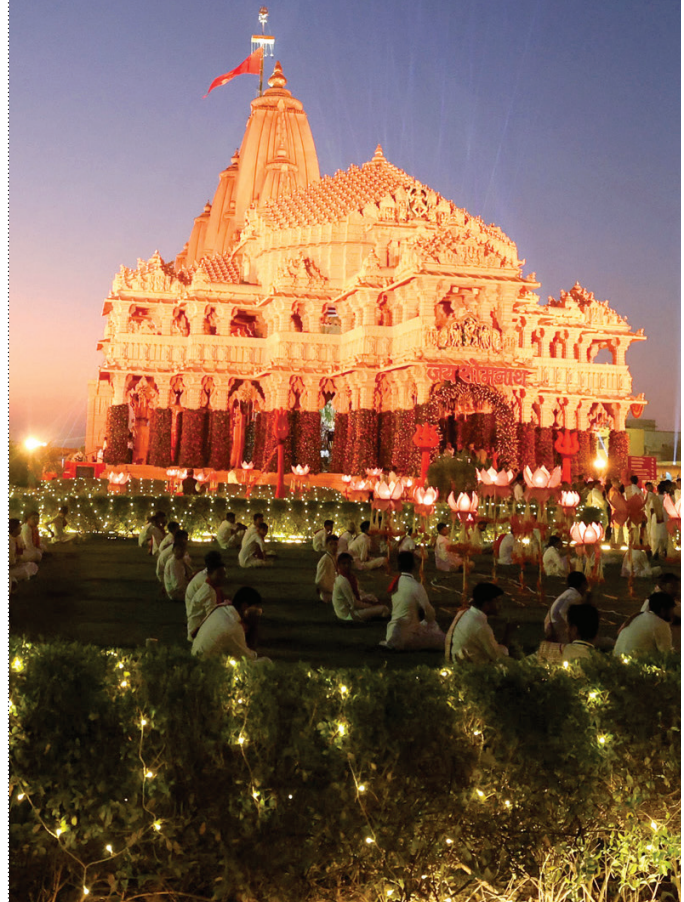
केदारनाथ के विकास में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना शामिल है, जो सभ्यतागत एकता का प्रतीक है और तीर्थ स्थल के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है।



जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गुजरात

सोमनाथ मंदिर के आसपास विकास और पार्वती मंदिर के निर्माण सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करके अहिल्याबाई होल्कर की विरासत को आगे बढ़ाया गया है।

- तीर्थयात्रियों को अरब सागर के सामने सोमनाथ मंदिर का शानदार दृश्य दिखाने के लिए सैरगाह का विकास किया है।



विदेश मंत्रालय में बनाया अलग से विभाग

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाया है।

पर्यावरण प्रतिबद्धता में नेतृत्व का युग

एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर वसुधैव कुटुम्बकम् के मंत्र को अपनाते हुए भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी विश्व का मार्गदर्शक बनकर उभरा है। दुनिया की कई संस्थाओं की मुखर आवाज बनकर भारत ने मिशन लाइफ और प्रकृति के साथ समन्वय की नई राह दुनिया को दिखाई है। बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने प्रकृति के साथ समन्वय के नए युग की कर दी है शुरुआत...

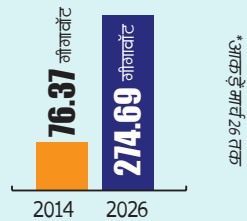
दुनिया का नेतृत्व करता भारत

- भारत ने **UNFCCC** और पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को लगातार आगे बढ़ाया है। 2015 के शुरुआती **NDC** लक्ष्यों से लेकर अब 2031-2035 के नए लक्ष्यों तक भारत अपनी प्रतिबद्धता निभा रहा है। भारत अब जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में एक मजबूत और प्रमुख आवाज बन चुका है।
- वर्ष 2015 में भारत ने **UNFCCC** के तहत अपना पहला नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (**NDC**) प्रस्तुत किया, जिसमें 2030 तक के लक्ष्य तय किए गए थे।
- **COP21** के बाद से पीएम मोदी के "क्लाइमेट जस्टिस" यानी जलवायु व्याय के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों में समानता और न्याय की चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए।
- ग्लोसगो में आयोजित **COP26** शिखर सम्मेलन (2021) में पीएम मोदी ने "लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट" यानी **LIFE** का विचार सामने रखा, जिसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे पर्यावरण हितैषी काम अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला किया जा सके।



- प्रधानमंत्री मोदी की "पंचामृत" पहल, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत को एक वैश्विक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
- **BRICS 2026**: भारत ने सदस्य देशों के साथ सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, वनाग्नि प्रबंधन और आपदा से निपटने की क्षमता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा जलवायु अनुकूलन विषयों पर चर्चा शुरू की है।
- **UNEA-7** में वनाग्नि पर प्रस्ताव: दिसंबर 2025 में केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (**UNEA-7**) के 7वें सत्र में भारत की तरफ से प्रस्तुत "वनाग्नि प्रबंधन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने" संबंधी प्रस्ताव को अपनाया गया।

देश में करीब 4 गुना हुई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता



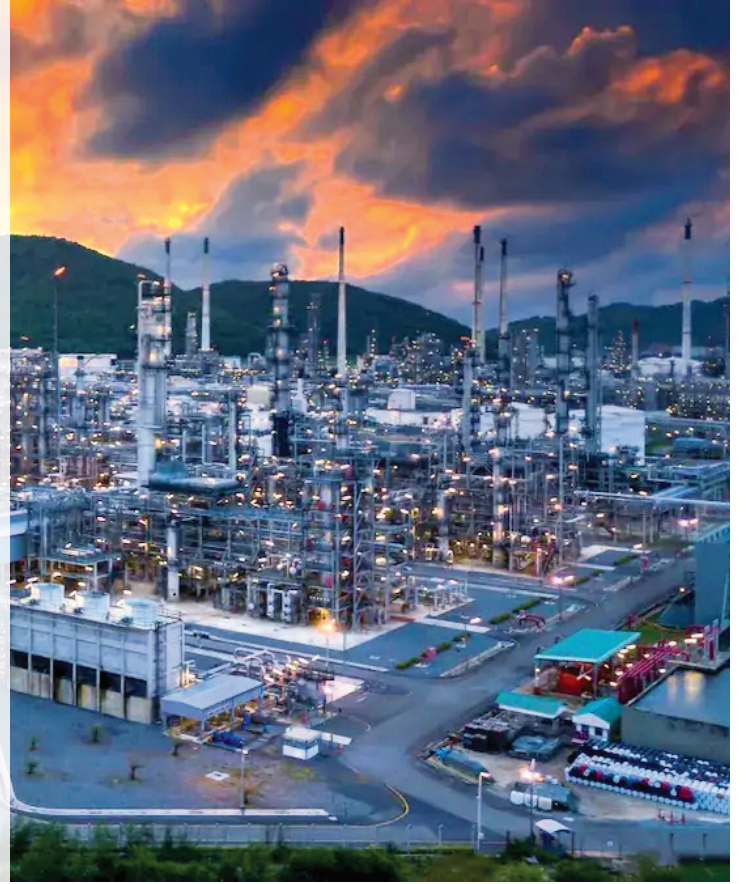
नवीकरणीय ऊर्जा का नेतृत्व करता भारत

- तीसरे स्थान पर है भारत, दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में।
- पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।
- सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है।
- भारत ने गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2026 तक 283.47 गीगावॉट हासिल की। यह कुल स्थापित बिजली क्षमता 532.74 गीगावॉट का 53.21% है।



समय से पहले लक्ष्य हासिल

- GDP की उत्सर्जन तीव्रता (**Emission Intensity**) कम करने का लक्ष्य भारत ने 11 साल पहले, यानी 2019 में ही हासिल कर लिया।
- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने से जुड़ा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (**NDC**) 2015 का लक्ष्य तय समय से 9 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य भी निर्धारित समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया गया।
- गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने का पेरिस समझौते के तहत तय 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले जून, 2025 में पूरा किया।
- 2005 से 2020 के बीच भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी की।
- वर्ष 2021 तक भारत ने 2.29 अरब टन **CO** के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार किया, जो 2030 के लक्ष्य 2.5 अरब टन के काफी करीब है।
- मार्च 2026 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2031-2035 अवधि के लिए भारत के अगले **NDC** को मंजूरी दी।
- भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता हासिल करेगा।



स्वच्छता के लिए आदत में बदलाव

- स्वच्छता से लेकर सिंगल-यूज प्लास्टिक से बचने तक, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रेरित किया है।

- गोबरधन योजना "कचरे से कंचन" की पहल है, जो सर्कुलर इकोनॉमी और मिशन **LiFE** के अनुरूप है। 30 अप्रैल 2018 को शुरू किया। जनवरी, 2026 तक 189 संपीडित बायोगैस परियोजनाओं की शुरुआत हो चुकी है।

स्वच्छ भारत

12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण



262 करोड़ पौधे लगाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान में।

नमामि गंगे जैसे अभियानों को जन आंदोलन का रूप देकर यह सुनिश्चित किया कि लोगों की आदतों में बड़े स्तर पर स्थायी बदलाव आए।



“

हमें इस मंत्र को याद रखना है- प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात् जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। मुझे विश्वास है कि हम अपने मिशन लाइफ का पालन करके एक बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दिखाया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। पर्यावरण कानूनों में सुधार से नियमों का बेहतर पालन और कारोबार करने में आसानी दोनों बढ़ी हैं।

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण...

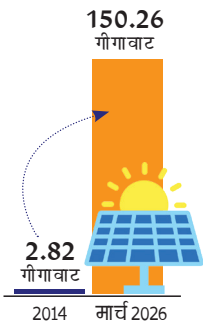
178 करोड़ लीटर डीजल की एक साल में बचत



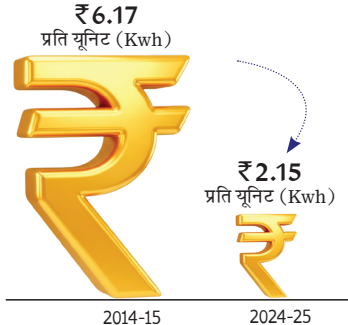
3.61 लाख बायो-टॉयलेट रेलवे पैसेंजर कोच में 2014 के बाद लगाए गए, जबकि 2004 से 2014 तक सिर्फ 9,587 लगाए गए थे।

सूरज की ऊर्जा से घर रोशन

36.88 लाख घरों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर सिस्टम लगाए गए 30 अप्रैल, 2026 तक। योजना में स्थापित क्षमता 10.77 गीगावाट तक पहुंची। 19,480 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी।



53 गुना बढ़ी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता



सौर ऊर्जा टैरिफ में 65 फीसदी की कमी

क्षमता विस्तार के साथ नियमों की सख्ती भी

केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 अधिसूचित किया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का स्थान लेंगे। ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से पूर्ण रूप से लागू हो गए हैं। नियमों में 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अंतर्गत अपशिष्ट को गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट एवं विशेष देखभाल अपशिष्ट में अलग-अलग करना आवश्यक किया गया है।

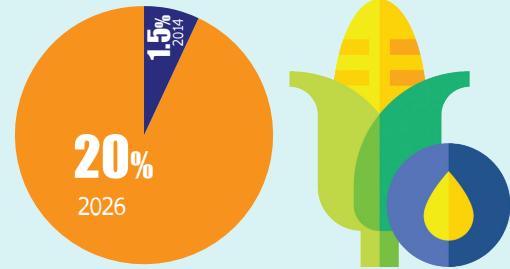
5 गुना हुई ठोस अपशिष्ट प्रोसिंग



समय के साथ ईंधन की भी बचत

फास्टैग ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 12 मिनट से घटाकर 47 सेकंड से भी कम कर दिया, इस आधुनिक सिस्टम से ईंधन की बचत से हर साल लगभग 1,500 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।

13 गुना बढ़ा इथेनॉल मिश्रण

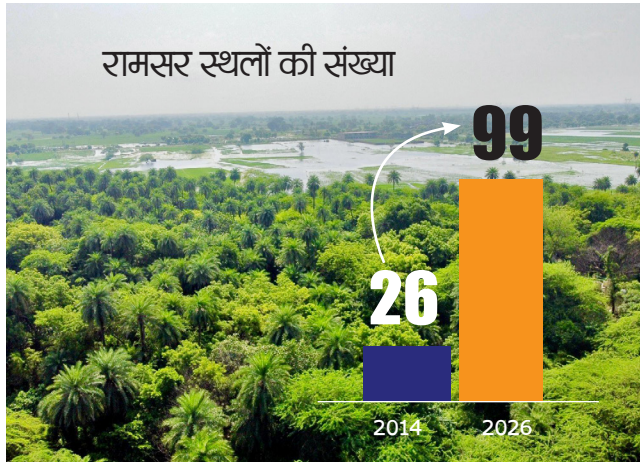


भारत के 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, जो स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और बेहतर पर्यटन सुविधाओं के लिए दिया जाता है।

वन्य जीवों के कल्याण और संरक्षण की पहल

देश में वन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। संरक्षित जंगलों का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ रामसर स्थल देश में जैव विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि प्रोजेक्ट टाइगर ने देश में बाघों की संख्या बढ़ाई है। अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की अंतर-महाद्वीपीय पहल से देश में जैव विविधता को बढ़ावा मिला है। न सिर्फ देश में चीतों की संख्या बढ़ रही है बल्कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चूजा भी नई पहल के तहत जन्म ले रहा है क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी की गई जीवों के कल्याण की कामना...

रामसर स्थल से लेकर बाघ-डॉल्फिन संरक्षण तक भारत



बीते 12 वर्षों में भारत ने 73 नए रामसर स्थलों को जोड़कर इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को काफी मजबूत किया है।

- भारत में बीते एक दशक में बाघों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है। 2022 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या रिकॉर्ड 3,682 हो गई है।
- आज दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित जंगलों का क्षेत्र बढ़कर लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।



■ प्रोजेक्ट चीता दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी प्रजाति के स्थानांतरण की परियोजना है। इस पहल से देश की वन्यजीव विविधता को बढ़ावा मिला है।

- वर्ष 2023 में 70 साल बाद भारत में चीता शावकों का जन्म हुआ, क्योंकि इससे पहले देश में चीते विलुप्त हो चुके थे। अब भारत में जन्मे ऐसे शावकों की कुल संख्या 37 तक पहुंच चुकी है।

718
हिम तेंदुआ

6,327
डॉल्फिन

- पहली वैज्ञानिक संख्या आकलन के अनुसार देश में दर्शाई गई है।

13,874 है तेंदुओं की संख्या, भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट-2022 के अनुसार।



‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (जीआईबी) का एक चूजा गुजरात के कच्छ में लगभग एक दशक बाद जन्मा है। यह उपलब्धि जंपस्टार्ट अप्रोच नामक एक नवीन संरक्षण उपाय के माध्यम से संभव हो पाया है। इसकी योजना एक वर्ष पहले बनाई गई थी। प्रोजेक्ट जीआईबी की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2011 में गुजरात सहित इसके प्राकृतिक आवासों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए की थी।



देश में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। लुप्तप्राय 24 प्रजातियों पर केंद्रित संरक्षित कार्रवाई की जाती है जिसमें समुद्री कछुआ भी शामिल है।



वन्यजीवों के लिए की गई पहल

1,134 हुई देश में वन्यजीव की सुरक्षा, संवर्धन और विकास के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2025 में, 2020 में 921 थी।

58 हुई देश में टाइगर रिजर्व संख्या 2025 में, 2014 में 48 थी। 31 से बढ़कर 33 हुई एलीफेंट रिजर्व संख्या 2020 से 2025 के बीच।



- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में घड़ियालों के संरक्षण और उनके अस्तित्व पर होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक नई पहल को मंजूरी दी गई है। अब घड़ियाल केंद्र सरकार के 'वन्यजीव पर्यावास कार्यक्रम' के प्रजाति पुर्नबहाली कार्यक्रम में शामिल है।
- मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-डिब्रू-सैखोवा वन्यजीव परिपथ का विकास किया गया।
- पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-दुबरी-बांधगढ़-कान्हा-मुक्की-पेंच में वन्य जीव परिपथ का विकास किया गया।

“

हमें इस बात पर गर्व है कि भारत में विश्व के कुछ सबसे अद्भुत वन्य प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में 70% से अधिक बाघों का निवास हमारे यहां है। हमारे यहां एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी और एशियाई हाथियों की अधिकतम संख्या भी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वनराज एशियाई शेर फल-फूल रहे हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



द आर्ट ऑफ लिविंग का स्थापना समारोह

बेंगलुरु ने आध्यात्म और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊंचाई तक पहुंचाया

सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध बेंगलुरु ने भारत की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्म और आध्यात्मिक चेतना को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज विश्व भर के लोग भारत के आध्यात्मिक मूल्यों से प्रभावित हैं और इन्हीं प्राचीन मूल्यों से भारत की अनेक संस्थाएं भी प्रेरणा प्राप्त करती रही हैं। 10 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब संकल्प स्पष्ट हो और कार्य सेवा की भावना से किया जाए, तब प्रत्येक प्रयास देता है सुखद परिणाम...

द आर्ट ऑफ लिविंग का बीज 45 वर्ष पूर्व श्री श्री रविशंकर ने बोया था, जो आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। द आर्ट ऑफ लिविंग के स्थापना वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज यह हमारे सामने एक विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा है, जिसकी हजारों शाखाएं विश्व भर में असंख्य लोगों के जीवन को छू रही हैं।” भारत की भाषाओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों और उपासना पद्धतियों से समृद्ध विविधता है। इन सुंदर विविधताओं को एक सूत्र में क्या बांधता है। इसका उत्तर है-स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना। भारत के मूल्यों में गहराई से निहित योग, ध्यान और

प्राणायाम की परंपरा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आज विश्व भर के लोग भारत के आध्यात्मिक मूल्यों से प्रभावित हैं और इन्हीं प्राचीन मूल्यों से भारत की अनेक संस्थाएं भी प्रेरणा प्राप्त करती रही हैं।

पुराणों की प्राचीन शिक्षाओं में उल्लेख है कि दूसरों की सेवा करना पुण्य है, जबकि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। सेवा भारतीय समाज का स्वाभाविक चरित्र है। भारत के अनेक आध्यात्मिक आंदोलनों ने अंततः मानवता की सेवा के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। यही भावना द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रत्येक प्रयास में भी दिखाई देती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में द आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि स्थायी कृषि स्वयं “आर्ट ऑफ लिविंग” की अभिव्यक्ति है तथा रसायनों से धरती माता की रक्षा करना आध्यात्मिक साधना और पर्यावरण संरक्षण, दोनों का प्रतीक है। प्राकृतिक खेती को अपनाना और धरती माता को रसायनों से बचाना, यह भी आर्ट ऑफ लिविंग है।

प्रधानमंत्री मोदी ने “पर ड्रॉप, मोर क्रॉप” पहल के माध्यम से किसानों के बीच बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। पानी की हर बूंद बचाना भी आर्ट ऑफ लिविंग है। ■

बेंगलुरु का माहौल... यहां का वातावरण... कुछ अलग ही होता है। ये शहर software और services के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान... Spirituality... आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा भारत

भारत आज 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्वस्तरीय सड़क, रेल, हवाई और ऊर्जा संपर्क सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। 'पीएम मित्र पार्क' की मदद से भारत की समृद्ध कपड़ा उद्योग की विरासत को फिर से मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन...

तेलंगाना के लोगों के जीवन को आसान बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए 10 मई को हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से भविष्य में यहां बनने वाले वाहन और मशीनें, इस जोन में लगने वाली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ-साथ पूरे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। इसका लाभ आम लोगों के साथ-साथ तेलंगाना के मजदूरों और किसानों को भी होगा।

साइबराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद शहर का एक प्रमुख आईटी और व्यावसायिक केंद्र है। यही वजह है कि साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है। साथ ही, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। यह इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यहां विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन बिजली आपूर्ति होगी, दुनियाभर के निवेशकों के लिए यहां हर वो सुविधा उपलब्ध होगी जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वारंगल में बना 'पीएम मित्र पार्क' देश में वस्त्र क्रांति को गति देगा। इसमें शामिल होने वाली इकाइयों को पीएलआई योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ मिलेंगे। लाभार्थी उद्यमों ने पीएलआई योजना का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। यह वस्त्र पार्क बड़ी संख्या में (विशेष रूप से बहन-बेटियों के लिए) रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि सड़क, रेल और हवाई अड्डों जैसे आधुनिक संपर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार ने पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व निवेश किया है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए ही लगभग 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तेलंगाना को राष्ट्रीय फोकस से काफी फायदा हुआ है। बीते 12 वर्ष में राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दोगुना हुआ है। वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश का रेल बजट 1,000 करोड़ रुपये से भी कम था, वहीं तेलंगाना का मौजूदा वार्षिक रेल आवंटन 5,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। लगभग 50,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं अभी चल रही हैं। तेलंगाना में पांच वंदे भारत और छह अमृत भारत रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं।

अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी थी... तब हमारे वस्त्र उद्योग की बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क, देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



राष्ट्र तेलंगाना में पीएम मोदी

पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन

वारंगल में 1,700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन। जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क भारत का पहला पूर्ण रूप से चालू पीएम मित्र पार्क है। यह पार्क प्रस्तावित नागपुर-विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय राजमार्ग -163जी) के निकट और राष्ट्रीय राजमार्ग-163 के करीब स्थित है। यह पार्क प्रमुख रेलवे नेटवर्क और बंदरगाहों से उत्कृष्ट मल्टीमॉडल संपर्क प्रदान करता है।

कैंसर मरीजों के इलाज की व्यवस्था

हैदराबाद स्थित सिंधु अस्पताल, राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह अस्पताल कैंसर के उपचार के लिए अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी संस्थान है। 18 मंजिला इस अस्पताल में 1,500 बिस्तर, 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 उन्नत ऑपरेशन थिएटर हैं। अस्पताल में कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा, कैंसर सर्जरी, अस्थि मज्जा



प्रत्यारोपण, उन्नत गहन देखभाल और 33 से अधिक विशेषज्ञताओं सहित व्यापक देखभाल की व्यवस्था है।

इन परियोजनाओं से विकास को मिलेगी रफ्तार...

₹3,175 की लागत से हैदराबाद-पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-167 के चार लेन के निर्माण की नींव।

यात्रा समय में लगभग 1 घंटा 30 मिनट की कमी आएगी।

- रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारे (एचएनआईसी) के अंतर्गत विकसित किए जा रहे जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव। 3,245 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को 2,350 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से विकसित किया जा रहा है।
- जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाली परियोजनाओं से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

₹1,535

करोड़ की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित।

इनमें काजीपेट-विजयवाड़ा बहु-ट्रैकिंग परियोजना के 118 किमी लंबे कई खंड शामिल हैं।

- हैदराबाद में इंडियन ऑयल की 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित मलकापुर टर्मिनल परियोजना राष्ट्र को समर्पित। इस टर्मिनल की कुल टैंक क्षमता 1,65,000 किलोलिटर है।

पीएम मोदी ने कहा, हमें सिर्फ उतनी ही ऊर्जा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी जरूरी हो, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और युद्ध के संकटों के बुरे असर को कम किया जा सके।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

21वीं सदी के वैश्विक संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट आने से सभी आर्थिक गतिविधियां ठप हो सकती हैं। यही वजह है कि भारत सरकार राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल के उद्घाटन को महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाएगा। ■

सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष

सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत की अडिग भावना का उत्सव

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, सनातन आस्था की अमर ज्योति का प्रतीक है। खंडहर से पुनर्निर्माण तक का इसका सफर भारत की अजेय विरासत और उसके अदम्य संकल्प को दर्शाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संपादकीय लेख लिखा। इसमें उन्होंने सोमनाथ के संदर्भ में 11 मई के दिन के चिरस्थायी महत्व और भारत की सम्यता की महानता पर बात की। साथ ही, गुजरात यात्रा के दौरान उन्होंने वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का भी किया उद्घाटन...

हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात् दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ राष्ट्र के नागरिकों के हृदय में हमेशा बना रहा। सोमनाथ मंदिर परिसर में इसकी पुनर्स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में, मैं कितनी ही बार यहां आया हूँ, उनके सामने

नतमस्तक हुआ हूँ। लेकिन, आज जब मैं यहां आ रहा था तो यह यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था। तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1,000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा नहीं बने हैं बल्कि हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का मौका मिला है।

75 साल पहले, 11 मई के दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय, सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों



प्रधानमंत्री का आलेख पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



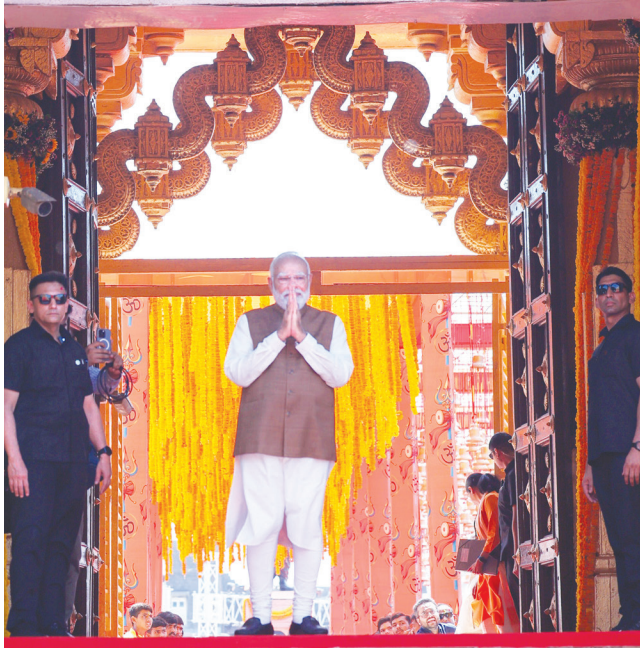
वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन किया। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ-साथ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। साथ ही, उन्होंने सरदारधाम परिसर में स्वागत क्षेत्र, नागरिक सुविधाएं, भोजन क्षेत्र और ई-पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का दौरा भी किया।



आज समय की मांग है कि हम “वोकल फॉर लोकल” को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह...लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को ताकत दें।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



सोमनाथ मंदिर से जुड़े दिव्य और अद्भुत तथ्य

- हर वर्ष लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु सोमनाथ पहुंचते हैं। वहीं, महाशिवरात्रि 2025 के पावन अवसर पर एक ही दिन में 3.56 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान शिव का दर्शन और पूजन किया।
- सोमनाथ ट्रस्ट हर वर्ष सैकड़ों महिलाओं को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बना रहा है।
- सोमनाथ मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बिल्व वन, जहां लगभग 1,700 बिल्व वृक्ष हैं, उसकी देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी महिला संरक्षक निभा रही हैं।
- सोमनाथ का मियावाकी वन हर वर्ष लगभग 93,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है।
- सोमनाथ में हर महीने प्लास्टिक कचरे का पुनर्वर्णन कर लगभग 4,700 टाइल्स तैयार की जाती हैं। इन टाइल्स का उपयोग मंदिर परिसर में रास्तों और पथों के निर्माण में किया जाता है।

को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। साथ ही, सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज इस अवसर पर, मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूँ। मैं यहां देख रहा हूँ, विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूँ, असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभास-पाटन ने बार-बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूँ, हजारों वर्षों की

सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में सरदार वल्लभभाई पटेल को भावमीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत गौरव और आध्यात्मिक निरंतरता के प्रतीक के रूप में अपने पूरे वैभव के साथ पुनः स्थापित होते देखना सरदार पटेल का सपना था। देश सरदार पटेल के इस विजन को साकार करने के प्रति सदा प्रतिबद्ध रहेगा।

रोमांचक फ्लाइंपास्ट का किया अवलोकन

सोमनाथ अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा प्रस्तुत एक रोमांचक फ्लाइंपास्ट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आकाश में गौरव और शौर्य का भव्य संगम सोमनाथ मंदिर पर केसरिया एवं तिरंगे का प्रकाश फैला रहा था। भक्ति और शक्ति की यह अद्भुत छटा प्रत्येक हृदय को गहन आनंद से भर देती है और प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करती है।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं, भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं, सोमनाथ अमृत-महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले एक हजार वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है।

सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी हुए शामिल

भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। समारोहों के भाग के रूप में उन्होंने कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया।

सोमनाथ मंदिर में महापूजा और कुंभाभिषेक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यात्रा के दौरान सोमनाथ मंदिर में महापूजा और कुंभाभिषेक भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा महान सौभाग्य प्राप्त होना उनके जीवन के सबसे भावुक और अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष अवसर पर महादेव की पूजा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शन एवं पूजन असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है।



सोमनाथ मंदिर की एक तस्वीर की साझा

सोमनाथ से वडोदरा जाते समय ली गई सोमनाथ मंदिर की एक तस्वीर पीएम मोदी ने साझा की। साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि प्रभास पाटन के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर भक्ति, इतिहास और सभ्यतागत भावना के एक तेजस्वी प्रतीक के रूप में शान से खड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह शाश्वत मंदिर बर्बर हमलों, आक्रमणों और सदियों के बीतने के बावजूद अडिग रहा है। सोमनाथ प्रत्येक भारतीय को शक्ति, साहस और आशा प्रदान करता है। ■



Narendra Modi
@narendramodi

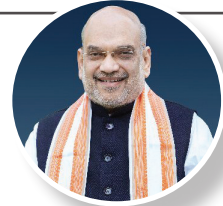
देशभर के किसान भाई-बहनों के हिरो की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए हम निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को जहां उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं उनके जीवन में और खुशहाली आएगी।



Rajnath Singh
@rajnathsingh

महिलाओं का सम्मान हमारी सभ्यता की आत्मा है और कोई समाज बिना इसके प्रगति नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार नारी सशक्तिकरण के साथ-साथ महिला आरक्षण (33%) के लिए भी प्रतिबद्ध रही है।

यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा का प्रतीक था, जो भले ही पारित न हो सका, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने का संकल्प और मजबूत हुआ है।



Amit Shah
@AmitShah

मैं अपनी माता के चरण स्पर्श हर दिन किया करता था और उनके न रहने पर भी हर दिन उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाता हूँ। हमारे देश में हर दिन माताओं को समर्पित है।



Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Tolling reimagined with Multi Lane Free Flow (MLFF)—a barrier-less system enabling seamless, non-stop travel. Powered by FASTag, AI, and number plate recognition, it ensures zero waiting time, faster journeys, and lower costs. Drive through at speeds of up to 80 km/h and experience the future of smart, efficient toll collection on India's highways.



Jyotiraditya M. Scindia
@JM_Scindia

भारत देश में अगर रक्त का संचार कोई हृदय के रूप में करता है तो मेरा @IndiaPostOffice करता है



Hardeep Singh Puri
@HardeepSPuri

देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं...

भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की LNG और 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध है।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने दैनिक एलपीजी उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि (35,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन) की है।

दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती : मोदी



दिल्ली, वैश्व संकट में भारत की प्रतिबद्धता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संबोधन का भाव व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को 1947 से ही दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जा रहा है और यह दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है।

दो टुक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को 1947 से ही दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जा रहा है और यह दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है।

सौमन्य भारत के आत्मबल का प्रतीक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को 1947 से ही दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जा रहा है और यह दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है।

पोखरण परमाणु परीक्षण को याद कर दिया संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को 1947 से ही दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जा रहा है और यह दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है।

11 तीर्थों के जल से कुम्भाभिषेक, पुष्पावली
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को 1947 से ही दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जा रहा है और यह दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है।

कोरोना जैसे कायदे: वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी की अपील

एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें: मोदी

पीटेल-डीजल के विकल्पपूर्ण इस्तेमाल पर भी जोर

इन बातों से समझे पीएम का संदेश

भारत देश में अगर रक्त का संचार कोई हृदय के रूप में करता है तो मेरा @IndiaPostOffice करता है

विकसित भारत के लिए मिलकर करें काम

आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष पूर्ण, पीएम ने सेवा भाव को सराहा



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेवा, आस्था, विश्वास और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को शुभमसा को जन्मक समारोह को। उन्होंने परिवारण विमोचन, युवा सार्वजनिकरण और आर्थिक कल्याण के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण के लिए सामाजिक प्रगति का आह्वान किया।

संकट में भी अर्थव्यवस्था मजबूत

फेडरल से बढ़ते निर्यात और निवेश के अवसर

एआई और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ावा जाए

PM की अपील, माननीयों का काफिला कम

तेल की बचत: प्रधानमंत्री ने अपना काफिला 50% घटाया, साथ चली सिर्फ 4 गाड़ियां

आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब: भारत

वर्ल्ड हिस्ट्री, (पंचम केसरी): भारत ने मंगलवार को कहा कि 'अतिरिक्त निर्यात' के दौरान चीन के पाकिस्तान को मदद देने से पहले चीन को स्पष्ट करवा ले।

इन्होंने भी अपने काफिले छोटे किए

राजस्थान, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा मूख्यमंत्रियों ने भी अपने वाहनों के संख्या को घटा दिया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि गुजरात के भीतर सेलिक्टिव प्रसाइट की जगह टैन, राज्य परिवहन की बस में सफर करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपील

राष्ट्रहित में आगे आने का समय

विकसित भारत की ओर बढ़ता भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त आधारस्तंभ तैयार कर चुका है। देश ने अपनी विकास यात्रा में जन-जन को सारथी बनाया है जिसका आधार जनसहभागिता है। यही कारण है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 महत्वपूर्ण आह्वान किए हैं। पहले के दशकों में भी जब-जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। जब करोड़ों भारतीय एकजुट होकर छोटे-छोटे बदलाव करेंगे तो राष्ट्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने से कोई रोक नहीं सकता...

140

करोड़ लोगों का सामूहिक प्रयास ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां निभाइए...

आइए भारत को और सशक्त बनाइए...



न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 जून, 2026
आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 19 मई 2026, कुल पृष्ठ-78)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित